coming to that. Thank you. ...(*Interruptions*)... Some of the solutions have been mentioned in the answer about the dynamic average that we want to bring in so that ten per cent is going to be a realistic ten per cent rather than the false base year of 1986-88.

[THE VICE-CHAIRMAN (DR. E.M. SUDARSANA NATCHIAPPAN) *in the Chair.*]

We have also spoken about giving a timeline so that activated discussions will happen for agriculture and permanent solution does not wait till 2017 and it happens earlier. Thank you.

DISCUSSION ON THE WORKING OF THE MINISTRY OF POWER – *Contd.*

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF POWER; THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF COAL; AND THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF NEW AND RENEWABLE ENERGY (SHRI PIYUSH GOYAL): Sir, now that we have discussed enough about the world, I think it is time we discussed mother India. Sir, I am very privileged that you have given me this opportunity to conclude a very important discussion on power sector which we started yesterday. Nearly 28 hon. Members participated in the discussion.

At the outset, I must mention that it was indeed a privilege to know the concerns of the hon. Members, to hear their very, very valuable suggestions and also for a new Minister like me who's only been in office for 67 days it was very redeeming to see the interest that this sector has amongst all sections of the House. मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि सदन ने इस विषय पर राजनीति नहीं खेली, सदन ने साधारणतया इस विषय को एक गंभीर मसले की तरह देखा, इस विषय को देशहित और जनिहत के साथ जोड़ा । मुझे लगता है कि पूरे सदन की भावना यह थी कि मेरा सहयोग करें, मुझे अच्छे सुझाव दें । मेरे काम में मैं कैसे और गति ला सकता हूं, उसके लिए मैंने बहुत गंभीरता से आप सबके सुझाव सुने हैं, नोट किए हैं । मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि भारत के प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जो सपना है, जिसे कार्यान्वित करने के लिए जनता ने हमें एक मौका दिया है, जनता ने हमसे उम्मीद रखी है, हम पर विश्वास रखा है, उसको हमारी सरकार, एनडीए की सरकार, मोदी जी के नेतृत्व में अच्छे तरीके से कार्यान्वित करेगी, उसके लिए हम वचनबद्ध है । जब डिबेट शुरू हुई थी, तो डा. साहनी ने कुछ अंधेरे की बात कही थी । वैसे तो डा. साहब आपके क्षेत्र में अंधेरा कुछ ज्यादा है बाकी प्रदेशों से, बाकी देश से । आपकी कविता में शायद आपकी खुद की कुछ समस्या भी झलकी थी, आपके दल की । आपने कहा कि अँधेरे में आ गए हैं हम, यहां जवां जिन्दगी की । मैं समझ सकता हूं कि जिदगी में जब पूरी जनता ने आपका हाथ छोड़ दिया, तो आपके लिए अंधेरा जरा ज्यादा महत्वपूर्ण है । ...**(व्यवधान)**...

श्री के.सी. त्यागी (बिहार): यह कहना ठीक नहीं है । ...**(व्यवधान)**...

SHRI PIYUSH GOYAL : Tyagiji, take it in a lighter spirit. ...**(व्यवधान)**...

श्री के.सी. त्यागी : आपने खुद कहा कि पूरे सदन ने नॉन-पार्टिसन तरीके से अपनी बात रखी है । ...**(व्यवधान)**...

श्री पीयूष गोयल : मैं mood थोड़ा lighter करना चाहता था । ...**(व्यवधान)**...

श्री के.सी. त्यागी : इस तरह इतनी arrogance ...**(व्यवधान)**...

श्री पीयूष गोयल : चलिए, त्यागी जी, arrogance ज़रा भी नहीं है । मैं mood जरा lighter करना चाहता था । ...**(व्यवधान)**... लेकिन हमें इस अंधेरे में भी एक किरण दिखती है, वह हमारे परम पूजनीय नेता, भारत के भूतपूर्व प्रधान मंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी, जो आपके भी बहुत निकट हैं, उनकी कविता से हम प्रेरणा लेते हैं और उन्होंने कहा था – चाहे कितना भी अंधेरा हो, चाहे कितनी भी दिक्कतों से, संकटों से हमें जूझना पड़े और चाहे देश के सामने समस्याएं गहरी हों, उसमें भी उन्होंने कहा—

"आओ फिर से दीया जलाएं,
भरी दुपहरी में अंधियारा
सूरज परछाईं से हारा
अंतरतम का नेह निचोड़ें
बुझी हुई बाती सुलगाएं
आओ फिर से दीया जलाएं ।"

मैं ज्यादा पंक्तियां नहीं पढ़ूंगा । मैं उसका एक और stanza पढ़ूंगा और उसका significance इस डिस्कशन के साथ जोड़ूंगा—

"हम पड़ाव को समझे मंज़िल
लक्ष्य हुआ आंखों से ओझल
वर्तमान के मोहजाल में
आने वाला कल न भुलाएं
आओ फिर से दीया जलाएं ।"

वास्तव में वाजपेयी जी का यह सार था कि जितने भी संकट हों, आज देश में जरूर संकट है, बिजली की समस्या बहुत गहरी है, शायद बिजली के संकट पर चुनाव भी जीते और हारे जाते हैं । उन्होंने जो संकेत दिया, उसमें एक-एक शब्द, एक-एक पंक्ति को देखें, तो यह ध्यान में आता है कि देश में कितनी opportunities हैं, कितना देश में साहस है इन मुश्किलों का सामना करने के लिए to overcome these difficulties और मैं आज कोशिश करूंगा कि क्या मुझे मिला, क्या मैं कर रहा हूं और आगे की मेरी क्या कल्पना है, इस विषय को थोड़ा विस्तार से मैं सदन के साथ शेयर करना चाहूंगा । मैं अपने काम में सदन का आर्शीवाद भी चाहूंगा, सहयोग भी चाहूंगा और सदन के सुझाव मुझे मिलते रहें, आगे चलकर चाहे सदन में मिलें, चाहे अलग से मिलें, उस उम्मीद के साथ मैं अपनी बात यहां पर रखना चाहूंगा ।

बुढानिया जी ने थोड़ी बहुत मेरे ऊपर टिप्पणी करते हुए कहा कि मैंने राजनीति में बहुत जल्द छलांग लगाई । बुढानिया जी, मुझे छलांग लगाने के लिए करीब 26 वर्ष लगे । मैंने 1984 में राजनैतिक काम शुरू किया था । ...**(व्यवधान)**...

श्री नरेंद्र बुढानिया (राजस्थान): यह मैंने इसलिए कहा कि मैं 1984-85 में पार्लियामेंट में आ गया था । मैं तब से लेकर अब तक काम कर रहा हूं, लेकिन आपने एक झटके में मारा उधर, तब मैंने यह बात कही । ...**(व्यवधान)**...

श्री पीयूष गोयल: फर्क यह है कि हमें गली-मोहल्ले से काम शुरू करना पड़ता है, हमें पोस्टर लगाना पड़ता है, चाहे कितना भी पारिवारिक संबंध हो, परिवार का स्थान राजनीति में हो। हमारी पार्टी में यह कोशिश रहती है कि लोग काम करें, जनता से जुड़ें, पोस्टर लगाएं । मां घर पर लेई बनाती थी और हमें जाकर पोस्टर चिपकाना पड़ता था । आजकल आचार संहिता में पोस्टर का जमाना खत्म हो गया है । नहीं तो हम खड़े होकर देखते रहते थे कि बैनर ठीक लग रहा है या टेढ़ा लग रहा है, ऊंचा लग रहा है, नीचा लग रहा है, ऐसा करते-करते 1986 से राजनीति में छोटे-छोटे कदम लेकर मैं यहां पहुंचा हूं । मेरी मां ने 2004 में राजनीति छोड़ी थी और पिता जी 2008 में नहीं रहे । उसके बाद मुझे पार्टी ने यहां आने का मौका दिया । मैं राजनीतिक परिवार या परिवारवाद के सहारे नहीं आया, इसलिए 26 वर्ष लगे । ...**(व्यवधान)**... मैंने कोई जल्दी छलांग नहीं लगाई, काम कर-करके छलांग लगाई है । हमारे मित्र प्रफुल्ल पटेल ने बहुत सारे विषय उठाए हैं । उन्होंने कहा है कि कुछ legacy issues हैं । मुझे कुछ legacy issues विरासत में मिले, जब मैंने भार संभाला, तो मैं उन legacy issues पर भी सदन का थोड़ा बहुत ध्यान आकर्षित करूंगा । लेकिन मुझे जो सबसे विचित्र legacy issue मिला, छोटी सी बात है, लेकिन मैं अभी तक उससे जूझ रहा हूं । पिछले दिनों देश में ऐसा संकट था कि कोयला कम था । पिछले दो -तीन-चार साल से पयार्वरण का मामला हो या देश की कोयला खदान देने का मामला हो, इनमें कुछ विषयों के ऊपर जांच हुई और उसमें कोर्ट-कचहरी का मामला हुआ । उस वजह से कोयला कम होने के कारण सरकार ने एक ऐसी situation create की है, जिसको अंग्रेजी में chicken and egg story बोलते हैं । आज ऐसी परिस्थिति है कि कोई पावर प्लांट है, अगर उसको कोयला चाहिए, तो बोलते हैं कि पहले PPA लेकर आओ, पावर पर्चेज एग्रीमेंट । किसी न किसी राज्य या डिस्कॉम के पास से पावर पर्चेज एग्रीमेंट लेकर आओ । जब वह पावर पर्चेज एग्रीमेंट के लिए जाता है, तो उसे पता चलता है कि सिर्फ case1 बिडिंग ही एलाउड है । case1 बिडिंग की गाइडलाइन में लिखा है कि अगर आपको case1 बिडिंग में बिड करना है, तो पहले कोयला दिखाओ, कोयला कहां है? आज परिस्थिति ऐसी है कि देश में कई ऐसे प्लांटस हैं, जिनके पास न तो कोयला है और न ही कोई खरीददार है । बस पड़े हैं, बैंकों में NPA बढ़ते जा रहे हैं । कई वर्षों से यह सिलसिला चलता आ रहा है । अब उसका राष्ट्र की अर्थव्यवस्था पर क्या असर होगा, बैंकों पर क्या असर होगा । यह तो आप सभी समझ सकते हैं । आखिर ये सब जितने प्लांट्स हैं, ये उत्पादन करते, तो शायद आप सबके राज्य और आप सबकी कांस्टिट्युएंसीज में बिजली की समस्या भी हल हो सकती थी । मैं आपको बताऊंगा कि कितने मैगावाट के प्लांट्स किस प्रकार से अटके हुए हैं । मैं वे गाइडलाइंस भी लेकर आया हूं, how the standard bidding documents don't allow you to bid unless you have the consent of the Coal India Ltd., for execution of the Fuel Supply Agreement. Then, as per the directives issued to the CIL supply of coal only will be available when you have a long term PPA. सरकार ने इस परिस्थिति में कार्यभार संभाला है । मुझे पूरी उम्मीद

[श्री पीयूष गोयल]

है कि हम इन सब चीजों को सुलझा लेंगे । हमारी बहुत वरिष्ठ सदस्या अनु आगा जी के पतिदेव ने 19 वर्ष पहले कुछ टॉक दी थी, "The power struggle, a saner alternative" इन्होंने कल ही मुझे दी और मैं उनको पढ़ रहा था । मुझे उनको पढ़कर बड़ा आश्चर्य हुआ कि बीस वर्ष बाद भी हम कहां खड़े हुए हैं? इसके तीन मुख्य अंग हैं । इनके पतिदेव ने कहा था कि जो प्लांट पुराने हो जाते हैं, उनके कोयले की कंजम्पशन बढ़ती है और एफिशिएंसी खराब हो जाती है, तो क्यों न जो बीस साल से अधिक पुराने प्लांट्स हैं, उन्हें रिफर्बिश करें? रिप्लेस करें । जब मैंने भार संभाला तो मैंने यह पाया कि प्लांट चाहे कितना भी पुराना हो, आप उसको चेंज नहीं कर सकते, नए प्लांट को कोल लिंकेज नहीं मिलेगा । हमारे प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मुझे तीन मंत्रालयों पावर, कोल और रिन्युएबल एनर्जी का भार दिया । उसकी वजह से थोड़ी बहुत दिक्कतें भी आईं । जो साइलोज में सरकार चलती है, तो अलग-अलग डिपार्टमेंट एक-दूसरे से कागज-पत्र पर ही बात करते हैं । इसके बदले हमने एक नया आयाम शुरू किया है कि हम सब मिल-जुलकर, कैसे सब डिपार्टमेंट एकजुट होकर देश की समस्याओं का हल निकालें । कुछ दिनों पहले जब यह विषय मेरे संज्ञान में आया था, तो मैंने तुरंत निर्देष दिया और उसको मिनिस्ट्री ऑफ कोल ने एप्रूव किया है कि जो भी पावर प्लांट 25 वर्ष से अधिक पुराना हो गया है, उसको ऑटोमैटिकली पूरी छूट मिलेगी कि वह नीयरेस्ट हायर केपेसिटी जो सुपर क्रिटिकल मॉर्डन प्लांट्स थर्मल होते हैं, उस केपेसिटी का प्लांट लगा सकते हैं और ऑटोमैटिक कोल लिंकेज ट्रांसफर होगी, ऑटोमैटिक कोल लिंकेज बढ़ भी जाएगी । क्योंकि जब प्लांट ज्यादा ऐफिशिएंट होगा, ज्यादा बड़ी कैपेसिटी का होगा तो स्वाभाविक है कि कोयला भी ज्यादा लगेगा । Automatic approval for a higher capacity, up to 50 per cent higher, उसका कोयला ऑटोमेटिकली सप्लाई हो और जब तक नया प्लांट नहीं लगता है, आप पुराना प्लांट चलाइए, लेकिन जिस दिन नये प्लांट को फायर करो, आपको उसी दिन पुराना प्लांट बंद करना पड़ेगा । यदि यह 50 प्रतिशत से अधिक भी हो, up to 50 per cent higher कैपेसिटी बढ़े, तो भी सरकार पूरी छूट देगी कि आप उसको रिप्लेस कर सकते हैं । मैं समझता हूं कि इस कदम से देश में एफिशिएंसी और पर्यावरण, दोनों में सुधार आने की बहुत अच्छी योजना बनेगी ।

इसमें एक दूसरी बात time-of-day tariff की लिखी थी । उन्होंने समझाया था कि यदि अलग-अलग समय का टेरिफ अलग हो तो क्या प्रभाव होगा । सर, देश में आज ऐसी सिचुएशन है कि रात को बिजली अधिक है । आज देश में रात की बिजली सस्ती है, लेकिन कोई खरीदार नहीं है, जबकि दिन में, पीक ऑवर में लोड ज्यादा है और बिजली की समस्या है । अभी दिल्ली में एक recent tariff order इंट्रोड्यूस हुआ था । अभी तक तीन राज्यों ने time-of-day tariff इंट्रोड्यूस किया है । इससे संभावना है कि peak load लगभग 15 प्रतिशत तक गिर सकता है और रात में जो बिजली वेस्ट हो रही है, वह अच्छे तरीके से इस्तेमाल हो सकती है । मैं आप सभी से अपने-अपने राज्यों में time-of-day tariff पर और ज्यादा बल देने के लिए रिक्वेरस्ट करता हूं जिससे घरों और उद्योगों को ज्यादा बिजली मिल सके । महोदय, tariff स्टेट सब्जेक्ट है, मेरे हाथ में नहीं है, वैसे ऊर्जा concurrent subject है इसलिए मेरे हाथ में जितना हो सकता है मैं करूंगा, परंतु उसमें राज्यों की सहायता, सहयोग और मिल-जुलकर काम करने का एक बहुत बड़ा रोल रहेगा ।

उन्होंने तीसरी बात डिमांड साइड मैनेजमेंट की कही थी । आज जो बिजली उत्पादित होती है, क्या वह अच्छे स्वरूप में इस्तेमाल होती है या उसमें वेस्टेज है? Energy efficient, energy conservation

एक ऐसा विषय है, जिसको मैंने दस-पंद्रह या बीस वर्षों की चर्चा में कभी सुना ही नहीं। मुझे याद है कि जब हम छोटे थे, तो रूम से बाहर निकलते हुए मां-बाप बोलते थे कि लाइट बंद करो, पंखा बंद करो, लेकिन यदि आज ए.सी. भी चौबीस घंटे चलता है तो किसी को कोई चिंता नहीं होती है। हम एनर्जी एफिशिएंसी के लिए एनर्जी कंजर्वेशन पर एक बहुत बड़ा प्रोग्राम करने जा रहे हैं। मैं उसकी भी चर्चा करूंगा, लेकिन अभी यह बताना चाह रहा था कि 1995 में मि. आगा, जो पुणे के एक बहुत विख्यात इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, कल उन्होंने जब मुझे यह पेपर दिया तो मुझे बड़ी हैरानी हुई कि जो इतनी ऑब्वियस चीज़ है, वह इस देश में बीस-बीस वर्षों तक नहीं की जाती है।

श्री अशोक गागुली जी ने low hanging fruits की बात कही है। मैं उनकी बात से एकदम सहमत हूं और आप मेरे कार्य में भी पाएंगे कि इनवेस्टमेंट्स को अनलॉक करने के लिए जो इमिडिएट स्टेप्स उठा सकता हूं, मैंने उस पर ज्यादा बल दिया है। जैसे वित्त मंत्री जी ने अपने बजट भाषण में देश को आश्वासन दिया है कि जितने भी पावर प्लाट्स 31 मार्च, 2015 तक कमीशन्ड हो जाएंगे, सरकार उन सभी को कोयला देगी। उसी कर्म में कई और डिसिजन्स low hanging fruits से इन्वेस्ट हो चुके हैं। हमने इस पर बल दिया है कि उनको किस तरीके से और जल्दी काम में लाना है।

वास्तव में, फ्राइडे को, जब श्री सुब्बारामी रेड्डी जी के प्रस्ताव पर डिबेट हो रही थी, तब श्री वी.पी. सिंह बदनौर जी ने कहा था कि sixty-seven years after Independence, India is still energy-starved. मैं उनकी बात से सहमत हूं कि अब समय आ गया है कि हम across party lines, across political parties इस विषय पर तेजी से जूझें। मुझे लगता है कि हम सब मिलकर कार्य करें। यदि इसमें राज्यों की सहायता भी मिलती है, तो हम पांच वर्षों के अंदर इसको कर पाएंगे कि इस देश के हर घर में चौबीस घंटे सातों दिन बिजली हो। यदि इस प्रकार का एक संकल्प लेकर आगे चलें कि हर उद्योग, हर ऑफिस और किसानों को पर्याप्त मात्रा में अपने खेतों के लिए बिजली मिले तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी की सहायता से हम इसको सपना नहीं, एक हकीकत में बदल देंगे।

हमारा लक्ष्य चौबीस घंटे सातों दिन बिजली देने का है 40 करोड़ भारतवासी और 8 करोड़ 6 लाख घर आज भी बिजली से वंचित हैं, यह दुर्भाग्य की बात है। हम ऑकड़ों की बात करते हैं, मेरे डिपार्टमेंट ने मुझे डेटा दिया है कि सिर्फ 57 हजार विलेजेज बिना बिजली के हैं। मैं भी बड़ा प्रसन्न हुआ कि 6-6.5 लाख विलेजेज में सिर्फ 57 हजार विलेजेज बिना बिजली के हैं, पर तब मालूम पड़ा कि हमारी कल्पना यह है कि अगर एक गांव में बिजली की तार पहुंच जाए और उस तार के पहुँचने के बाद 10 प्रतिशत घरों में बिजली पहुँच गई, तो हम कहते हैं कि वह विलेज इलेक्ट्रिफाइड है। यह देश कब तक इस प्रकार से चलेगा कि हम अपने आपसे यह कहते रहें कि 10 प्रतिशत घर ...**(व्यवधान)**... यह आपके 10 वर्ष के राज का कानून है। अगर आपको ज्यादा वाद-विवाद करना है, तो मेरे पास आपके हर काम के बारे में पूरी डिटेल्स हैं। अगर 10 प्रतिशत घर विद्युत पा लेते हैं, तो हम कहते हैं कि वह विलेज इलेक्ट्रिफाइड है। इसके बावजूद आज 40 करोड़ भारतवासी हैं, जिनके घरों में बिजली नहीं है। आपकी बात सच है कि 8-10 घंटे बिजली न होना तो नॉर्मल माना जाता है। कई राज्य तो ऐसा कहते हैं कि बिजली गई नहीं है, बल्कि बिजली आई है। अब यह परिस्थितियों मैंने 60 दिनों में तो पैदा नहीं की। यह परिस्थिति तो मुझे मिली है। अब इससे जूझने के लिए अगर इस सदन के 247 मेम्बर्स में से कोई कहते हैं कि मैं 67 दिनों में इसको रिजॉल्व कर सकता हूँ, तो I will be happy to exchange places and this will be a brilliant thing. It will be something like the movie, 'Chief Minister of one day' who solves all the problems of the country.

[श्री पीयूष गोयल]

इसी क्रम में 2012 में पूरे देश ने जो ग्रिड फेल्योर देखा था, मेरे ख्याल से पूरे विश्व में इतना गम्भीर ग्रिड फेल्योर कभी भी नहीं हुआ था, जो 2012 में हुआ । It was the largest known blackouts in the world history.

कई राज्य ऐसे हैं, जैसे जम्मू-कश्मीर, महाराष्ट्र और असम, जहां पर डेफिसिट कुछ ज्यादा ही है । उत्तर प्रदेश और बिहार की चर्चा मैं इसलिए नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि शायद आगे और बहुत आने वाला है । लेकिन, साथ ही साथ, कई राज्य ऐसे हैं, जिनसे हम कुछ-न-कुछ सीख सकते हैं । **...(व्यवधान)...**

SHRI P. BHATTACHARYA (West Bengal): Would you kindly tell us about Jammu and Kashmir ? What is the present position ? is it true what you have said ? You said. 'ज्यादा डेफिसिट है' ।

SHRI PIYUSH GOYAL: Sir, I think we will take this up at the end because I prefer to go by my flow. I will respond to Mr. Bhattacharya, but I am not yielding. ...(*Interruptions*)...

THE VICE-CHAIRMAN (DR. E.M. SUDARSANA NATCHIAPPAN): The Minister is not yielding. ...(*Interruptions*)...You can raise it as a clarification. ...(*Interruptions*)...

श्री पीयूष गोयल : इसी परिस्थिति में आज कई राज्य ऐसे हैं, जैसे गुजरात, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, जहां हर घर को 24 घंटे बिजली मिलती है ।

THE VICE-CHAIRMAN (DR. E.M. SUDARSANA NATCHIAPPAN): Please sit down. ...(*Interruptions*)... It is not going on record. ...(*Interruptions*)...

श्री पीयूष गोयल : इन तीनों राज्यों में भी आखिर 24 घंटे बिजली मिलने के पीछे उनके कुछ-न-कुछ कार्य हैं, उन कार्यों में **...(व्यवधान)...**

SHRI ISHWARLAL SHANKARLAL JAIN (Maharashtra): What is the number of farmers' applications pending with them?

THE VICE-CHAIRMAN (DR. E.M. SUDARSANA NATCHIAPPAN): Please hear the Minister. If you want to have any clarification, you can raise it afterwards.

श्री पीयूष गोयल : मैंने जैसे ही कार्य संभाला, तो शुरू-शुरू में मैं गुजरात गया और मैंने गुजरात में समय दिया, ताकि मैं वहां से सीखूँ, समझूं कि किस प्रकार से 24 घंटे बिजली इतनी कम अवधि में **...(व्यवधान)...** एक प्रदेश पूरे 24 घंटे बिजली हर घर को दे सकता है । साथ-ही-साथ, अगर आप देखें, तो पूरे गुजरात में कैसे कम अवधि में **...(व्यवधान)...**

THE VICE-CHAIRMAN (DR. E.M. SUDARSANA NATCHIAPPAN): Mr. Bhattacharya, you had initiated the debate. You can raise it after the Minister replies. Please sit down. ...(*Interruptions*)... You can raise it after the Minister's reply is over.

श्री पीयूष गोयल : कैसे कम अवधि में चौबीस घंटे सातों दिन बिजली दी जा सकती है और बिना टैरिफ बढ़ाए । कई राज्य तो कहते हैं कि टैरिफ नहीं बढ़ा, इसलिए हमारा नुकसान हो रहा है । गुजरात में 12 वर्ष में सबसे कम टैरिफ बढ़ा है और उसके बावजूद भी उसके discoms के प्रॉफिट बढ़े हैं । **...(व्यवधान)...**

श्रीमती विप्लव ठाकुर (हिमाचल प्रदेश): हिमाचल प्रदेश में 24 घंटे बिजली रहती है । It is not only Gujarat ...(*Interruptions*)...

उपसभाध्यक्ष (डा. ई.एम. सुदर्शन नाच्चीयप्पन) : विप्लव जी, आप बैठिए ।

श्री पीयूष गोयल : जब मैं गुजरात गया, तो वहां से मैंने सीखा कि किस प्रकार हर घर में 24 घंटे बिजली दी जा सकती है । इसके बाद मैंने सभी राज्यों से अपील की कि आप लोग आकर हमसे बात कीजिए, हम आपको बताएंगे और इसकी योजना बनाएंगे कि आपकी स्टेट में 24 घंटे बिजली कैसे दी जा सकती है । अभी तक राजस्थान, आंध्र प्रदेश और दिल्ली, तीन ही राज्य ऐसे हैं, जिनके प्रतिनिधिमंडल मेरे पास आए और जिन्होंने इस विषय पर मेरे साथ चर्चा की । सदन को यह जानकर खुशी होगी कि इन तीनों राज्यों का कॉम्पोज़िट प्लान बनाया गया कि राजस्थान में क्या-क्या करने की आवश्कता है, आंध्र प्रदेश में क्या-क्या करने की आवश्कता है, दिल्ली में क्या-क्या करने की आवश्यकता है और तीनों राज्यों में किस प्रकार से 24 घंटे बिजली मिले । इसमें उनकी तरफ से **...(व्यवधान)...**

SHRI V. HANUMANTHA RAO (Telangana): Sir, whatever he is saying about Andhra Pradesh Government ...(*Interruptions*)...

THE VICE-CHAIRMAN (DR. E. M. SUDARSANA NATCHIAPPAN): No, no; please sit down. He is only speaking about the prospective plans. You listen to him.

श्री पीयूष गोयल : उनकी पहल के ऊपर केंद्र सरकार ने तुरन्त कार्यवाही की । मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, आप सब भी अपने-अपने राज्यों की सरकारों से बात करें कि वे आकर हमसे इस विषय पर चर्चा करें । हमारे पास ऐसे बहुत सारे प्लांस, बहुत सारी योजनाएं और बहुत सारे तरीके हैं, जिनसे हम आप लोगों के प्रदेशों में मदद कर सकते हैं, बशर्ते वे हमसे बात करें और बशर्ते उसके ऊपर दोनों तरफ से मेहनत हो, दोनों तरफ के लोग उस काम में जुट जाएं ।

गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कोल के माध्यम से, T&D losses कम करने की योजनाओं के माध्यम से, equipment upgrade करने की योजनाओं के माध्यम से technical और financial support दे सकती है । आप लोग अपने- अपने राज्यों की समस्याएं बताएं, आपके राज्य के मुख्य मंत्री या उनके प्रतिनिधि हमारे पास आएं तो इस समस्या का हल जरूर निकलेगा ।

नरेश अग्रवाल जी ने इस सम्बन्ध में कुछ बहुत महत्वपूर्ण बातों का जिक्र किया था । एक तो उन्होंने कहा था कि जब "राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना" में एस्केलेशन होता है, तब सरकार क्यों कुछ नहीं देती । सरकार का एक बजट है, जिसमें 90% केंद्र सरकार देती है और स्टेट को सिर्फ 10% देना पड़ता है । अब उसमें एस्केलेशन न हो, समय पर जमीन मिले, समय पर प्रोजेक्ट एग्ज़ीक्यूट हो, वास्तव में यह स्टेट गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, इसलिए एस्केलेशन का प्रावधान नहीं

[श्री पीयूष गोयल]

है । मुझे लगता है कि हम सबको हरेक प्रोजेक्ट पर, उसे आउटकम बेस्ड बनाने के लिए फोकस करना पड़ेगा । समय पर चीज़ें बनें, कॉस्ट बजट में बनें, इससे देश को ज्यादा लाभ होगा ।

उन्होंने 'Power System Development Fund' की बात भी कही । उसमें 7,100 करोड़ रुपये इकट्ठे हुए हैं । बेसिकली यह वह पैसा है, जो पैनल्टी के रूप में जमा होता है, जब कोई discom या स्टेट proper frequency control नहीं करते हैं । इसकी गाइडलाइंस हमने बना ली हैं, हालांकि पिछले कई वर्षों से वह गाइडलाइंस नहीं बनीं थीं । Now they are in place. अब स्टेट्स और युटिलिटीज़ जो भी प्रोजेक्ट्स लेकर आएंगे, उसमें system upgradation और grid security बढ़ाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाएगा । आप सबसे दरख्वास्त है कि आप इसके बारे में प्रपोज़ल्स लेकर मिनिस्ट्री ऑफ पावर में आइए ।

उन्होंने एक बात Gadgil Formula के बारे में भी कही । सर, Gadgil Formula चौथे फाइव ईयर प्लान में बना था । जब यह बात मेरे सामने आई, तो मैंने उनसे कहा कि अब बारहवां फाइव ईयर प्लान चल रहा है, इसलिए इस पर एक बार फिर से पुनर्विचार करना चाहिए । तब डिपार्टमेंट के लोगों ने मुझसे कहा कि सर, आप यह बात मत खोलिए, पहले ही देश में सेंटर, स्टेट, इंटरस्टेट बहुत सारे डिस्प्यूट्स हैं, आप एक डिस्प्यूट और मत खोलिए । It will be opening up a Pandora's box. फिर भी अगर सभी राज्य मानते हैं कि इस पर पुनर्विचार होना चाहिए और अगर इस पर झगड़ा न करते हुए सभी राज्य तैयार हों, तो मैं इस पर पुनर्विचार करने के लिए पूरे तरीके से तैयार हूं । **...(व्यवधान)...**

SHRI P. BHATTACHARYA: Sir,..

THE VICE-CHAIRMAN (DR. E.M. SUDARSANA NATCHIAPPAN): Please sit down. You can clarify later. Let the Minister complete his reply. You will be given a chance for clarifications.

श्री पीयूष गोयल : मेरी तरफ से, I don't have an ostrich-like approach. I am open to all ideas. I am open to all suggestions. Should you all decide, all the 29 States, including Delhi, 30 States, decide that this should be re-visited, I have an open mind. But I just pray and wish that it does not lead to more discontent or misunderstandings among States.

नरेश जी ने एक विषय guarantees के बारे में उठाया था और कहा था कि PPA is not possible, क्योंकि बैंक लोन नहीं देता है । इसके बारे में मैंने पहले भी बताया था कि अभी तो परिस्थितियां ऐसी हैं कि लाखों करोड़ रुपये के प्रोजेक्ट्स फंसे हुए हैं । मैं बैंक वालों से किस मुंह से बोलूं कि आप पावर सेक्टर को सपोर्ट करो? मेरी तरफ से मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि इन सब समस्याओं को सॉल्व करते हुए मैं इनका समाधान अवश्य निकालंगूा, जिससे बैंक फिर से पावर सेक्टर की ओर आएं और खुद आकर बोलें कि आप लोन लीजिए और प्रोजेक्ट लगाइए । इस देश में इतनी डिमांड है, मैंने कुछ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को एक मीटिंग के लिए बुलाया था और उनसे कहा कि इस देश की आबादी 120 करोड़ है, इसलिए इसकी बड़ी डिमांड है । अनु जी ने 800 यूनिट कहा, लेकिन आज देश में 940-950 यूनिट *per capita* कंज़म्प्शन है । यह चाइना की 4000 है । अन्तर्राष्ट्रीय स्तर

पर तो कुछ देशों की यह 15000 है । क्यों नहीं भारत भी उस प्रकार का एक बड़ा लक्ष्य रखे? क्यों न भारत में भी वास्तव में, जो गांगुली जी ने कहा कि a trillion dollars is spent in this sector. Let me assure you, Ram Gopal*ji*, and I hope you can convey, through the Chair, to Naresh*ji* that we will ensure that this becomes a flourishing sector, जहां हमें बैंकों को न बोलना पड़े, बैंक आपके पास पैसा देने आए ।

इसी क्रम में मैं सिर्फ एक जानकारी दे दूँ । उन्होंने एफआरपी (फाइनांशियल रिस्ट्रक्चरिंग प्लान) के बारे में जिक्र किया । यह अप्रैल, 2012 में फॉर्मूलेट हुआ । यह अप्रैल, 2012 के आंकड़ों के हिसाब से बनाया गया था । इसमें सात राज्य जुड़े—तमिलनाडु, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, झारखंड, बिहार और उस समय का आंध्र प्रदेश, जो अब आंध्र और तेलंगाना हो गया है, तो समझिए कि ये कुल आठ राज्य हो गये । अब इन आठों राज्यों से बातचीत और चर्चा में 18 महीने निकल गये । तो इसको वास्तव में अक्टूबर, 2013 में इम्प्लीमेंट किया गया । अब इन 18 महीनों में लॉसेज़ और बढ़ते गये । तो एफआरपी का कोई लाभ या उससे वास्तव में डिस्कॉम मुसीबत से निकले, वह परिस्थिति नहीं बनी । अब मेरे पास फिर से लोगों की मांग है कि एफआरपी-2 लेकर आओ । मैं इस पर गम्भीरता से विचार कर रहा हूँ कि किस प्रकार से इसको और robust बनाया जाय और किस प्रकार से इससे वास्तव में इन राज्यों की समस्याओं का हल हो । लेकिन God only helps those who help themselves. अगर इसमें परिस्थिति ऐसी बनती है कि सिर्फ केंद्र ही एफआरपी देता रहे और उसमें राज्यों की कोई भूमिका न हो, तो बड़ी मुश्किल होगी । इसलिए एक मॉडल स्टेट इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन रिस्पान्सिबिलिटी बिल 2013 में उस वक्त की सरकार ने पेश किया था । वह बिल बहुत अच्छा है, सुचारू बिल है । इसको हरेक स्टेट को, ये जो सातों- आठों स्टेट्स हैं, इन सारे स्टेट्स को अपनी असेम्बलीज़ में पास करना आवश्यक है । जो-जो स्टेट्स इसको पास करेंगे, मैं विश्वास दिलाता हूँ कि उनके साथ बैठ कर हम आगे का रास्ता तय करेंगे कि किस प्रकार से वे अपनी समस्याओं से निकल सकेंगे । इसमें बहुत अच्छे प्वायंट्स हैं । There are good points about 100 per cent metering, about energy dues to be paid in time, special courts for electricity theft, accounting measures, etc.

सर, नरेश जी ने एक बहुत इंस्टरस्टिंग बात रेज़ की । वे पूर्व पॉवर मिनिस्टर रह चुके हैं, इसलिए मैं बहुत ध्यान से उनकी एक-एक बात सुन रहा था । मैं सभी की बातें सुन रहा था, किसी में कोई फर्क नहीं है । परन्तु क्योंकि उनका इस लाइन में तजुर्बा हैं, उन्होंने एक नेशनल इलेक्ट्रिसिटी फंड की बात की । नेशनल इलेक्ट्रिसिटी फंड में अभी तक 26 हजार करोड़ के प्रोजेक्ट्स एप्रूव हो चुके हैं । मुझे बड़ा दुख है कि उत्तर प्रदेश ने अभी तक एक भी प्रोजेक्ट नेशनल इलेक्ट्रिसिटी फंड में पेश नहीं किया है, जिससे हम उसके ऊपर विचार करके उसे एप्रूव कर सकें । तो उन्होंने मेरे सामने बात तो बहुत अच्छी रखी, परन्तु आप अपनी राज्य सरकार से पूछिए, क्योंकि दुर्भाग्य से एक भी प्रोजेक्ट उसने पेश नहीं किया है । यह एक interest subsidy scheme है, जिससे investments, sub-transmission and distribution में सरकार एक इंटरस्ट सबवेंशन की तरह, सब्सिडी की तरह पैसा देती है । मुझे लगता है कि इसमें उत्तर प्रदेश को बहुत लाभ होगा । पार्टिकुलरली, अभी हम जो दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना लाए हैं, उसके साथ अगर इसको यूज करके आप सेपरेट डिस्ट्रीब्यूशन फीडर रूरल सेक्टर में किसानों के लिए बनवाते हैं, तो इससे उनको सही समय पर पर्याप्त मात्रा में बिजली मिलेगी तथा उसमें आप बिजली के दाम कंट्रोल कर सकते हैं, जिससे किसान के ऊपर भार नहीं आये और उसके दुरुपयोग से बचा सकते हैं । तो इससे पैसे का दुरुपयोग नहीं

[श्री पीयूष गोयल]

होगा तथा बिजली सही आदमी को, सही समय पर और सही दाम पर मिलेगी। मेरी आपसे तथा बाकी सभी राज्यों से भी दरख्वास्त है कि आप इसका लाभ उठाएँ। कोल क्वांटिटी का एक बहुत बड़ा गंभीर मसला है कि इस देश में कोयला पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल रहा है। लगभग 70 हजार मेगावाट यानी 69,842 MW power plans are stranded. जिनमें से 45,634 MW plans कोयले की वजह से आज stranded हैं, क्योंकि कोयला नहीं है। अब इस परिस्थिति को बदलना आवश्यक है, इस परिस्थिति को सुधारना आवश्यक है। इसके लिए जब मैं गहराई में गया, तो ध्यान में आया कि गत चार वर्षों में कोयले का प्रोडक्शन किस प्रकार से हुआ। 2009-10 में 532 मिलियन टन कोयला देश में प्रोड्यूस हुआ। 2010-11 में 533 मिलियन टन कोयला प्रोड्यूस हुआ और यह पिछले वर्ष से एक मिलियन टन बढ़ा यानी इसमें 0.2 परसेंट की ग्रोथ हुई। 2011-12 में 540 मिलियन टन कोयला प्रोड्यूस हुआ और 1.3 परसेंट की ग्रोथ हुई। 2012-13 में 557 मिलियन टन कोयला प्रोड्यूस हुआ और 3.3 परसेंट की ग्रोथ हुई और 2013-14 में 564 मिलियन टन कोयला प्रोड्यूस हुआ और 1.5 ग्रोथ हुई। अब कोयले की ग्रोथ का यह ट्रैक रिकॉर्ड है। अब 67 डेज़ में मैं और ज्यादा कोयला कहां से लाऊं, यह आप सब लोग सोच सकते हैं। यह चार वर्ष यानी लगभग 1400 दिनों का ब्यौरा है और इस परिस्थिति के कारण में मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन कारण से आप सब भलीभांति अवगत हैं, चाहे वह पर्यावरण के अलग-अलग प्रयोग किए गए हों, चाहे वह कुछ विषयों में जो कोयले की खानें खुल सकती थीं, उनके ऊपर कुछ परछाई आने से वे आज कोर्ट में फंसी हुई हैं और इस कारण से कोयले की नई खान खुल नहीं पा रही है। इसकी जो भी वजह हो, इस पर राजनीति न करते हुए ....आज परिस्थिति ऐसी है कि गत चार-पांच वर्षों में पॉवर जनरेटिंग कैपेसिटी लगभग 60 प्रतिशत बढ़ी है और कोयले का उत्पादन मात्र सात-आठ प्रतिशत बढ़ा है। ऐसी परिस्थिति में मैं फिर भी जूझ रहा हूँ, फिर भी पूरे तरीके से, लगन से लगा हूँ कि कैसे कोयले के उत्पादन को इस वर्ष में भी बढ़ाऊं और आने वाले वर्षों में तेजी से बढ़ा पाऊं उसके लिए मैंने क्या किया?

सर, जब मैं गुजरात गया था, तो ध्यान में आया कि गुजरात में स्थित एक पॉवर प्लांट को झारखंड या छत्तीसगढ़ से कोयला आता है और झारखंड स्थित पॉवर प्लांट को गुजरात के पोर्ट में विदेशी कोयला आकर ट्रांसपोर्ट होता है। अब अलग-अलग coal linkages करने में over the years, coal linkages are completely irrational.

शायद एक ही समय पर रेल लाइन पर दो गाड़ियां जाती हैं—एक, कोरबा से गुजरात की तरफ ओर दूसरी, गुजरात से कोरबा की तरफ। इस प्रकार से लाखों टन कोयला जाता-आता है और इससे पर्यावरण पर बहुत प्रभाव पड़ता है। इसमें हजारों करोड़ रुपए freight में additional पड़ते हैं और रेल, जिसकी एक लिमिटेड कैपेसिटी है, वह ब्लॉक हो जाती है और इन तीनों का भार सामान्य उपभोक्ता पर पड़ता है। आखिर ये हजारों करोड़ रुपए जनता को भरने पड़ते हैं। जब पर्यावरण खराब होता है, तो इसका असर जनता के स्वास्थ्य पर पड़ता है। एक और माननीय सदस्य ने इस विषय को रेज़ किया था, मुझे अभी उनका नाम ध्यान में नहीं आ रहा है, rationalization of coal linkages विषय निकला था। मैंने तुरंत निर्देश दिया और पूरी दो सौ खदानों की स्टडी चल रही है और 31 अगस्त तक मुझे इसकी पूरी रिपोर्ट मिलेगी कि कैसे coal linkages को rationalize किया जाए। Sir, initial estimate is ₹ 5,000-6,000 crores. जब ये coal linages rationalize हो जाएंगे, तो ये पांच से छः हजार करोड़ रुपए देश के और आपके वोटरों के, आपकी जनता के, इस देश के नागरिकों के बचेंगे।

सर, इसी प्रकार से एक तरफ बिजली के कारखाने कोयले के लिए तरस रहे हैं और दूसरी तरफ e-auction द्वारा बड़ी भारी मात्रा में कोयला auction किया जा रहा है और auction में ट्रेडर्स और व्यापारी कोयला खरीद रहे हैं । मैं समझता हूँ कि यह आम जनता के साथ बेइंसाफी है । आखिर जब कोल इंडिया बनाई गई थी और उसे ये माइंस दी गई थीं, तो ये भारत की सम्पत्ति थीं, ये भारत के कोल ब्लॉक्स थे, ये फ्री में कोल इंडिया को दिए गए थे । इसलिए कोल इंडिया का प्रथम कर्तव्य यह है कि जो कोल पावर प्लांट्स को जाना चाहिए, वह उन्हें पहुंचे जिससे जनता तक बिजली पहुँच पाए । हमने कोल इंडिया लिमिटेड से रिक्वेस्ट की । चूंकि वह एक इंडिपेंडेंट कम्पनी है तो हम उससे रिक्वेस्ट कर सकते हैं, हालांकि अगर निर्देश देने की भी जरूरत पड़े तो वह भी हम दे सकते है, लेकिन आखिर कोल इंडिया भी भारत की कम्पनी है, आप सब की कम्पनी है । कोल इंडिया ने उस पर गौर किया ओर मुझे यह बताते हुए बड़ी प्रसन्नता है कि इस वर्ष ई-ऑक्शन को वह आधा कर देगी, जिससे इलेक्ट्रिसिटी डेवलपमेंट और प्रोडक्शन में ज्यादा कोयला जा सकेगा ।

प्रफुल्ल भाई ने जिक्र किया कि कोल इम्पोर्ट कीजिए । यह स्वाभाविक है । अगर कोयला कम है और प्लाट्स को चलाना है तो उसके लिए हमें शॉर्ट टर्म में कोल इम्पोर्ट करना पड़ेगा । यह कोई परमानेंट डायरेक्शन नहीं है, लेकिन शार्ट टर्म में प्लांट खाली रखने की अपेक्षा इम्पोर्ट करना ज्यादा अच्छा है । अगर किसी को यह लगता है कि जनता को बिजली मत दो, प्लांट खाली रखो, एनपीए बना दो, तो मैं आपकी राय पर चर्चा करने के लिए तैयार हूँ और सदन जो फैसला करेगा, वह निर्देश मैं दे दूँगा ।

बड़े वरिष्ठ सदस्य और नेता, दिग्विजय सिंह जी ने पुराने प्लाट्स की बात की, जिसका जिक्र मैंने पहले भी किया है । सर, हमने उस पर पूरी नीति एनाउंस कर दी है और उस नीति के तहत ये सभी पुराने प्लाट्स, जो ज्यादातर पब्लिक सेक्टर में हैं, मैं समझता हूँ कि अगर हम उन सबको चार-पांच वर्षों में बदलें तो देश के पर्यावरण और इफिसिएंशी, दोनों में सुधार आएगा ।

हक साहब ने वैस्ट बंगाल के संबंध में एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही कि कोयले का उत्पादन किस प्रकार से 25 प्रतिशत बढ़ सकता है । हक साहब, मैं बहुत खुश हूँ कि आपने यह विषय उठाया । जब मैं आपके राज्य में गया था तो वहां आपकी सम्माननीया मुख्य मंत्री जी से मेरी बहुत अच्छी चर्चा हुई थी । एक बहुत ही कोऑपरेटिव मूड में हुई उस चर्चा में मैंने इस विषय पर उनसे रिक्वेस्ट की कि वैस्ट बंगाल के उत्पादन पर जो सैस लगता है, वह पूरे देश में सबसे ज्यादा है, जिसकी वजह से जब हम कोयले का उत्पादन करते हैं और उस पर सैस लगाकर उसे बेचना चाहते हैं तो उसे कोई नहीं खरीदता है । यह एक तरीके से आपके लिए नुकसान है । अगर आप उस सैस को कम रखते हैं तो लोग उस कोयले को लेने में उत्साहित होंगे और आपका ज्यादा सैस बढ़ेगा । Your effective collection, जो Laffer's curve है, shows lower taxes lead to higher output, अगर आप उसे गम्भीरता से देखें तो मुझे लगता है कि इसमें आपके प्रदेश को लाभ होगा ।

रेणुका जी ने रेशनलाइजिंग ऑफ कोल लिकेंजेज़ के बारे में अपनी बात रखी थी, जिसका मैंने अभी जिक्र किया । बैष्णव परिडा जी ने कोल ब्लॉक के इवैक्युएशन, कोल ब्लॉक्स में आउटपुट की बात की और उन्होंने यह भी बताया कि जिनके राज्य में पूरा कोयला नहीं मिलता है । सर, मैं चेयर के माध्यम से आपसे दरख्वास्त करूँगा कि सरकारी कम्पनियों को कोयला मूव करने में अगर सबसे ज्यादा कहीं कठिनाई आती है तो वह ओडिशा में आती है और आपकी पार्टी की वहां सरकार है । मेरा उनसे लगातार सम्पर्क है । मैंने स्टेट गवर्नमेंट के हर लेवल पर इस इश्यू को टेकअप किया

[श्री पीयूष गोयल]

है । मैं आपके मुख्य मंत्री जी को धन्यवाद दूँगा कि उन्होंने भी इस विषय में अपने अफसरों और लोकल लीडर्स को बड़े सख्त निर्देश दिए हैं, जिससे वहां कुछ इंप्रूवमेंट आई है और उसमें अभी और भी सम्भावना है । मैं आपसे दरख्वास्त करूँगा कि आप हमें मदद करें । महानदी कोलफील्ड से लगभग एक लाख टन कोयले का उत्पादन प्रतिदिन बढ़ सकता है, जो बाकी के 29 राज्यों में जाएगा और उन सबका बिजली का उत्पादन बढ़ेगा । अगर आपका राज्य मुझे इस चीज़ में मदद करे तो मुझे पूरा विश्वास है कि पूरा सदन आपका धन्यवाद करेगा । **...(व्यवधान)...**

हमने एग्जिस्टिंग माइंस से उत्पादन बढ़ाने के लिए पर्यावरण मंत्रालय से चर्चा शुरू की है कि किस प्रकार से ये एग्जिस्टिंग माइंस उत्पादन बढ़ा सकें । उन्हें पर्यावरण मंत्रालय थोड़ी छूट दे । इन माइंस की पब्लिक हीयरिंग वगैरह सारी चीज़ें पहले ही हो चुकी हैं । मुझे वहां से बहुत अच्छी सपोर्ट मिल रही है और मुझे उम्मीद है कि हम एग्जिस्टिंग माइंस से प्रोडक्शन बढ़ा पाएँगे । उसमें एक विषय में मैं सदन में अफसरों को आश्वासन देना चाहूंगा, सर, अफसरों के ऊपर एक कानूनी प्रावधान है कि अगर एक किलो भी आउटपुट माइनिंग प्लाटं से बढ़ता है तो उनके ऊपर क्रिमिनल ऐक्शन होगा और जेल में डाला जाएगा । अब पर्यावरण के कुछ ऐसे नियम पहले बने हैं, जिसमें यह कानून है । मैं समझ सकता हूं अगर कोई चोरी करे और उस पर लागू हो तो वह अच्छी बात है, लागू होना चाहिए । लेकिन जो अफसर समझो कोल इंडिया या subsidiary या सी.सी.एल. का आउटपुट कंट्रोल कर रहा है, वह डे-टु-डे तो वहां एक-एक किलो मॉनिटर नहीं कर सकता । तो अगर चार मिलियन टन का एक टन हो गया तो उसको जेल जाना पड़ेगा, आज के कानूनी प्रावधान में । तो मैं सदन की परमिशन चाहूंगा कि ऐसे में कुछ पैनल्टी हो जाए, कुछ आगे के लिए उनका ध्यान आकर्षित करें । लेकिन जेल में तो न डालें ।

THE VICE-CHAIRMAN (DR. E.M. SUDARSANA NATCHIAPPAN): How much time will you take?

SHRI PIYUSH GOYAL: There are 27 speakers and five hours' debate.

THE VICE-CHAIRMAN (DR. E.M. SUDARSANA NATCHIAPPAN): Actually, we have to go to another important subject relating to discussion on natural calamity. ...(*Interruptions*)..

SHRI TARUN VIJAY (Uttarakhand): It should not be made disaster of time. ...(*Interruptions*)..

THE VICE-CHAIRMAN (DR. E.M. SUDARSANA NATCHIAPPAN): Some clarifications are also being sought. ...(*Interruptions*)...

श्री पीयूष गोयल: तो मैंने अफसरों को आश्वासन दिया है कि जब उन्होंने विदाउट एनी मेलाफाइड, बोनाफाइड अगर कुछ थोड़ा-बहुत आउटपुट कम ज्यादा हो गई हो तो हम उनको प्रोटैक्ट करेंगे, उनके ऊपर एक्शन नहीं होने देंगे । नहीं तो, अफसर, क्या करेंगे, चार मिलियन टन के माइन को साढ़े तीन मिलियन पर रोक देंगे । क्यों रिस्क लें? अब दो सौ माइनों में एक-एक, दो-दो, चार-चार लाख टन कम कर दो तो और 15-20 मिलियन टन प्रोडक्शन कम हो जाएगा । अब सदन तय कर

5.00 P.M.

सकता है कि क्या करना चाहते हैं । देखिए, मुझे लगता है कि in the interest of increased coal output ऐसा सुझाव दिया है और विश्वास है कि आप सबका इसमें समर्थन मिलेगा । कई खदानों में कई प्लांट्स के पास सरप्लस कोल माइन करने की केपेबिलिटी है । लेकिन आज के दिन कोई कानून नहीं है कि सरप्लस कोल का क्या किया जाए । यह मेरे सामने विषय है, मैं कोशिश कर रहा हूं कि जल्द से जल्द एक ट्रांस्पेरेंट मकेनिज्म प्राइसिंग का तय हो सके, जिससे यह कोयला भी कोल इंडिया को मिल जाए और फिर कोल इंडिया अपने linkages and supply to the Electricity Board बढ़ा सके । Mechanization and technology upgradation में मेरा विशेष ध्यान है और मैं कोशिश कर रहा हूं कि ज्यादा से ज्यादा particularly underground mines में इसे इस्तेमाल किया जाए । नई खदानों की exploration का काम बढ़ी धीमी गति से चल रहा है । पिछले वर्ष 7 लाख मीटर का exploration हुआ । मैंने अफसरों को इस वर्ष के लिए इस टारगेट को 12 लाख मीटर करने के लिए कहा है और आगे आने वाले दिनों में निजी क्षेत्र के लोगों को भी इन्वॉल्व करके हम उस exploration के काम को बढ़ाएंगे, जिससे नई माइन से कोयले का उत्पादन बढ़ सके ।

नरेश अग्रवाल जी ने मेरा ध्यान आकर्षित किया था कि उत्तर प्रदेश के प्लांटों में कोयला कम है । मैं बतला दूं कि उन छः प्लांटों में एक में 5 दिन का है, एक में 17 दिन, एक में 18 दिन, एक में 25 दिन और आखिर में 5 दिन के लिए है । वास्तव में कोई ऐसी गंभीर समस्या उत्तर प्रदेश के किसी प्लांट में नहीं है । करीमपुरी जी और हक साहब ने भी इस विषय की ओर मेरा ध्यान आकर्षित किया था कि 24 प्लांट्स में कोयला चार दिन से कम है । एकदम सही बात है, सर। 22 या latest statistics में 23 प्लांटों में कोयला 4 दिन से कम है । लेकिन आप जैसे उसको टेलीविजन पर sensationalized करके देखते हैं परिस्थिति, वह नहीं है । कोयला कम क्यों हैं, क्योंकि पिछले दो महीने इलेक्ट्रिसिटी का निर्माण कोयले के प्लांट से massively बढ़ा है, अकेले जून महीने में 20 प्रतिशत बिजली का उत्पादन कोयले के प्लांट से बढ़ा । जब कोयला उनको पर्याप्त मात्रा में मिल रहा है, लेकिन उसका कंजम्पशन फास्टर है, मानसून डिले के कारण hydel power कम हुई । तो हमने जनता को तकलीफ न हो उसके लिए electricity from coal-based plants बढ़ाई । अब हम कोशिश कर रहे हैं कि कोयला भी जल्दी पहुंचे और इस विषय में लोगों का समाधान हो जाए ।

(उपसभापति महोदय पीठासीन हुए)

सर, पॉवर प्लांट्स और कोल कंपनीज के बीच एक बहुत गंभीर मुद्दा क्वालिटी का था । सर, सप्लायर्स और कंज्यूमर्स के बीच जीसीवी को लेकर काफी डिस्प्यूट्स हैं **...(व्यवधान)...**

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Mr. Minister, we have a time constraint also because there is a Short Duration Discussion. How many more minutes do you want?

SHRI PIYUSH GOYAL: Sir, I will take some time. There are a lot of issues.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Yes Yadav*ji*, what do you want ?

प्रो. राम गोपाल यादव (उत्तर प्रदेश): आप शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन आज मत लीजिए । मंत्री जी बहुत अच्छा जवाब दे रहे हैं । He is a very competent Minister. शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन कल करिए ।

SHRI P. RAJEEVE (Kerala): Sir, this is his maiden reply.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Okay. So, that is the sense of the House.

SOME HON. MEMBERS: Yes, Sir.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: So, the Minister will continue to reply for as long as he wants and the Short Duration Discussion will be tomorrow!

SOME HON. MEMBERS: Okay, Sir.

श्री प्रमोद तिवारी (उत्तर प्रदेश): होम मिनिस्ट्री पर चर्चा भी कल हो जाए?

MR. DEPUTY CHAIRMAN: No, no. That I cannot say now. See, that I cannot say now. That is why I came and asked the House if you want to take up the Short Duration Discussion now, then, the Minister has to stop. But you said that let the Minister continue. I also agree. Tomorrow, we will decide about the rest of the things. Mr. Minister, you can continue.

SHRI PIYUSH GOYAL: Sir, I can do it tomorrow if you want me to.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: No; you continue. That is the sense of the House. The House wants you to continue, then, why should I object?

SHRI PIYUSH GOYAL: Thank you, Sir.

There are many disputes between suppliers and consumers on the coal quality. In some cases, there is a GCV dispute and in some cases the ash content is under dispute. Many States, including Uttar Pradesh and Maharashtra, have complained that they get boulders instead of coal. I have taken up these issues very seriously, Sir. I am happy to report that I have taken several key decisions in the Coal Ministry. In fact, I have a list of so many decisions which have been taken to address all these issues, but I will not go into all of them. I will highlight only a few things.

[THE VICE-CHAIRMAN (DR. SATYANARAYAN JATIYA) *in the Chair.*]

We have now introduced third-party sampling for the first time in India in so many years in which the third party will be decided by the purchaser. The Coal India will not be allowed to foist the third party sampler. The purchaser will nominate a company from a panel which will be jointly decided. Purchaser will have the right to get it inspected and billing will be based on the quality and the sample that the independent investigation shows. Sir, for the public sector and the State Government utilities, at the unloading end, we will allow sampling by the same agency so that -- it is on a trial basis, as an experiment, --we could check if at the loading and the unloading ends the

quality is the same. Because, many times concerns are expressed that at loading end, what happens we don't know. The quality changes by the time it reaches the unloading end. This is something which I myself have not been able to understand. So, I have done this process on an experiment basis. Let us see how the quality matches. I am quite confident that we will not leave anything to chance and we will make sure consumer is king under this Government and consumer will be respected for his rights. So, we will have this process by which we will ensure that the correct quality of coal is supplied to all the consumers.

Sir, there is a mandatory requirement that by January 2015 every bit of coal that is transported beyond 750 kilometres will be washed and transported. When I took charge, Sir, I found that there was no way it could be implemented in time. There is a further stipulation that by June 2016, anything transported 500 kilometres and more, it will be so. But when I took charge, I found that environmental approvals were pending for years. Washery contracts were not allotted. I have given strict instructions that they will adhere to this timeline in the interest of environment. हम पर्यावरण को मद्देनज़र रखते हुए जनवरी, 2015 तक जो भी कोयला 750 किलोमीटर से अधिक दूरी पर जाएगा और जून, 2016 तक जो भी कोयला 500 किलोमीटर से अधिक दूरी पर ट्रांसपोर्ट होगा, उसे वाश कर के आपको भेजेंगे । साथ-ही-साथ दिसम्बर, 2014 तक पूरे देश में कोयले की खानों में क्रशर्स लगाए जा रहे हैं ताकि आपको complaint of boulders कभी न आए, कोल minus hundred capacity पर सीआईएल और उसकी subsidiaries आपके पॉवर प्लांट्स को पहुंचाएंगी । इस प्रकार से अलग-अलग निर्णयों को लेकर हमारी सरकार ने कोयले की क्वालिटी सुधारने का बीड़ा उठाया है और मैं आपको आश्वस्त करता हूँ कि आने वाले दिनों में हम और निर्णय लेते रहेंगे, जिससे कोयले की समस्या पर नियंत्रण पा सकें ।

महोदय, गुन्डु सुधारानी जी ने रामागुंडम एसजीपीएस का मामला उठाया था कि और कोयला आपको मिलना चाहिए । आपको जानकार खुशी होगी कि जो आपके 2600 मेगावाट प्लांट की कांट्रेक्टेड क्वांटिटी इस वर्ष जून तक पहले 6 महीने की 59.36 लाख टन थी, उसके बदले आपको 66.35 लाख टन कोयला मिला है । इसका मतलब आपको वास्तव में 110 प्रतिशत कोयला मिल चुका हैं । हर जगह, जहां-जहां हम बढ़ा पा रहे हैं, उसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा कोयला पहुंचे । इसी श्रृंखला में कुछ माननीय सदस्यों ने सीएमडीज़ के एपायंटमेंट का विषय उठाया था । सीआईएल के सीएमडी को तेलंगाना राज्य ने मेरे से ले लिया । पीएसबी द्वारा एनएचपीसी में जो सीएमडी एपायंट हुआ, किसी ने कंपलेंट कर दी, तो वह विजिलेंस में अटक गया । यह एक सरकारी प्रोसेस है, जो मेरे हाथ में बहुत कम है । फिर भी मैं पीएसबी और सरकार में Cab. Sec. से बात करुंगा और जल्द से जल्द एपायंटमेंट्स हो सकें, ...**(व्यवधान)**... उसमें ध्यान दे रहा हूँ ।

सर, इस गंभीरता को समझते हुए कि CIL should not remain headless, I have given charge to a very senior officer, और मुझे पूरा विश्वास है कि उसका काम बड़े अच्छे तरीके से, सुचारु रूप से चलाया जाएगा । आपके कुछ कोल गैस्फिकेशन की भी बात की । उस पर मुझे और स्टडी करनी पड़ेगी, क्योंकि अभी नया सब्जेक्ट है, लेकिन जो गैस बेस्ड प्लांट्स हैं, चूंकि देश में गैस का उत्पादन बहुत कम है, इसलिए आज के दिन उनको इम्पोर्ट करने के अलावा और कोई रास्ता

[श्री पीयूष गोयल]

मेरे पास नहीं है । जब भी उत्पादन बढ़ेगा, मैं उस मंत्रालय से बात करके कोशिश करुंगा कि पावर को ज्यादा से ज्यादा मिले । आपने विंड पावर पोटेंशियल की भी बात की, उस पर मैं आगे अपनी बातचीत में आऊंगा ।

महोदय, एक गंभीर समस्या कोल कोर्ट केसेस की थी । लगभग 208 कोल ब्लॉक्स, जो एलाट हुए, वह मामला कोर्ट में फंसा हुआ है । जब सम्माननीय कोर्ट फैसला देगा, उसके बाद मैं आगे कार्रवाई कर पाऊंगा । मुझे उम्मीद है कि इस महीने या अगले महीने इसका फैसला आना चाहिए । It is reserved for judgement, and I am very eagerly waiting. जो निर्णय होगा, हम समझते हैं कि उसको आगे लेते हुए हम तेजी से काम करेंगे और एकदम ट्रांसपेरेंट वे में आगे काम चलेगा, जिसमें कोई उंगली नहीं उठा सकेगा । इस पर बिड करने का हरेक को मौका मिलेगा । इसमें रिवर्स ऑक्शन कंप्यूटर द्वारा अच्छे तरीके से करेंगे, which will be transparent, which will be an absolutely honest price discovery mechanism. हम इन कोल ब्लॉक्स में उससे जल्दी उत्पादन लाने का कार्यक्रम शुरू करेंगे । साथ ही साथ कुछ कोल ब्लॉक्स हैं, जो गत एक-डेढ़ वर्ष में डीएलोकेट किए गए हैं, जिनमें अब कोर्ट केस नहीं हैं । जैसे ही अगस्त-सितम्बर में मेन केस का फैसला आ जाता है, उनके ऊपर जल्द से जल्द कार्रवाई करके जो कोल ब्लॉक्स कोल इंडिया कर सकती है, जो अगर एमडीओ के माध्यम से हो सकता है, कुछ ऑक्शन करके हो सकता है, हर प्रकार से इसमें उत्पादन लाने की पूरी कोशिश में हमारा कार्यालय जुटा हुआ है ।

कोयले के अलावा एक बहुत बड़ा गंभीर विषय है, जो कई सम्माननीय सदस्यों ने उठाया, वह ट्रांसमिशन और डिस्ट्रिब्यूशन का था । इसके तीन पहलू हैं-एक है ट्रांसमिशन डिस्ट्रिब्यूशन की एडीक्वेट अवेलेबिलिटी, दूसरा है ट्रांसमिशन डिस्ट्रिब्यूशन के लॉसेज और फाइनली पावर थेफ्ट । इन तीनों विषयों को हम गंभीरता से ले रहे हैं । वित्त मंत्री जी ने दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना की कल्पना देश के सामने रखी । एक और पावर सिस्टम डेवलपमेंट फंड और एक इंटिग्रेटेड पावर डेवलपमेंट स्कीम-ये दो और माध्यम हैं, जिनसे हम ट्रांसमिशन और डिस्ट्रिब्यूशन के सिस्टम्स को अपग्रेड कर सकते हैं । इंटिग्रेटेड पावर डेवलपमेंट स्कीम को हमने इसी बजट में इंट्रोड्यूस किया है । सर, कोशिश है कि देश भर में ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर्स बनें, जिनसे विंड, सोलर, हाइडल आदि का पर्याप्त मात्रा में ट्रांसमिशन हो सके ।

सर, दिल्ली में जब समस्या हुई, जिसके बारे में सबने मुझसे कई सवाल भी पूछे, आप सबने मेरा काम भी देखा, तो जब दिल्ली में समस्या हुई, तो मैंने स्वयं, जो मेरा काम नहीं था, मोदी जी ने मुझे देश का ऊर्जा मंत्री बनाया है, लेकिन दिल्ली में आप सबको समस्या का सामना करना पड़ा, इसलिए मैं स्वयं उसमें पड़ा, उसकी गंभीरता समझते हुए मैंने कोशिश की कि जल्द से जल्द ट्रांसमिशन लाइन्स खड़ी हो जाएं, जो ध्वस्त हुई थीं और अब, हमने दिल्ली के लिए एक पूरी स्कीम बना ली है कि किस प्रकार से दिल्ली में जल्द से जल्द ट्रांसमिशन डिस्ट्रिब्यूशन नेटवर्क को अपग्रेड किया जाए । माननीय वित्त मंत्री जी ने उसके लिए बजट में एक विशेष प्रावधान किया है और पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (पीजीसीआईएल) के माध्यम से मैंने दिल्ली सरकार को आश्वासन दिया है कि उनको जो मदद चाहिए, वह मैं दूंगा, जिससे कि हम दिल्ली की समस्या का दो-ढाई वर्षों में लांग टर्म सॉल्यूशन दे सकते हैं । इसी क्रम में साढ़े बारह हजार करोड़ के ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट्स, जो अटके हुए थे, उनको हमने क्लीयर किया और वे जल्द ही बिडिंग में आ जाएंगे ।

सर, एक समस्या थी कि प्राइवेट प्लेयर्स ट्रांसमिशन में एलाउ तो किए गए, लेकिन उनका कानून अलग था और पब्लिक कंपनीज़ का अलग था । हमने एन्वायर्नमेंट मिनिस्ट्री से बात करके दोनों पर समान कानून लागू किया है, जिससे निजी क्षेत्र भी इस स्ट्रेंथनिंग में गति से हमारा सहयोग कर सके ।

सर, कुछ राज्य ऐसे हैं, जहां पर लॉसेज बहुत ज्यादा हैं । जम्मू-कश्मीर में 61 प्रतिशत, उत्तर प्रदेश में 43 प्रतिशत, हरियाणा में 32 प्रतिशत, झारखंड में 47 प्रतिशत, राजस्थान में भी बहुत बड़ा आकंड़ा है, तो इस प्रकार से कई राज्य ऐसे हैं, जिनमें काफी बड़े लॉसेज, जैसे बिहार में 54 परसेंट है, तो इन सब राज्यों से मेरी दरख्वास्त है, मैं उनसे चर्चा भी करूंगा कि कैसे वहां पर लॉसेज को कम किया जाए, चोरी को कम किया जाए । उसी में लांग टर्म फायदा है । आखिर अगर एक व्यक्ति चोरी करता है, तो उसका भूगतान बाकी उपभोक्ताओं को करना पड़ता है । ...(**व्यवधान**)... आखिर सभी राज्यों को ...(**व्यवधान**)...

श्री गुलाम रसूल बलियावी (बिहार): छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में ...(**व्यवधान**)...

† **شری غلام رسول بلیاوی : چھتیس گڑھ اور مدھیہ پردیش میں ---(مداخلت)---**

उपसभाध्यक्ष (**डा. सत्यनारायण जटिया**): आप मत बोलिए, मिनिस्टर बोल रहे हैं । ...(**व्यवधान**)... देखिए, आप बैठे-बैठे मत बोलिए, आपको जब कहा जाए, तब बोलिएगा ।

श्री पीयूष गोयल: मुझे विश्वास है कि सभी राज्य इस कार्य में मेरा सहयोग करेंगे और जैसा माननीय दिग्विजय सिंह जी ने कहा, चोरी पर भी हम नियंत्रण ला पाएं और डिस्ट्रब्यूशन में 100 परसेंट मीटरिंग हो, साथ ही साथ टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके कैसे देश में चोरी का भी मामला खत्म करें और ट्रांसमिशन डिस्ट्रिब्यूशन लॉसेज को 15 प्रतिशत पर लाएं, जो एक तरीके से मैनेजेबल लॉस माना जाता है । इसमें सभी राज्य, मैं और हमारी सरकार मिलकर इसका सॉल्यूशन निकालें, इसमें मुझे आप सभी की मदद की आवश्यकता है ।

सर, वी.पी. सिंह बदनौर जी ने 1 लाख 90 हजार करोड़ रूपए के एफआरपी के बारे में कहा था, उसके बारे में मैंने बताया कि उसको थोड़ा रीविज़िट करना पड़ेगा तथा साथ ही साथ उन राज्यों को मॉडल लॉ बनाना पड़ेगा, तभी वह एफआरपी सक्सेसफुल होगा, नहीं तो वह सिर्फ पेपर वर्क रह जाएगा ।

सर, कुछ राज्य ऐसे हैं, जिनके डिस्काउंट्स का लॉस, अगर वह अनपार्लियामेंटरी नहीं है, तो मैं कहूंगा कि भयानक है । अभी किसी ने राजस्थान के बारे में बड़ी चिंता व्यक्त की, तो राजस्थान में 2008 में 15 हजार करोड़ का कर्जा था, लगभग वह लॉस है । 2013 में वह बढ़कर 70,000 करोड़ हो गया, तो 55 हजार करोड़ का नुकसान पांच वर्ष की छोटी सी अवधि में राजस्थान में बढ़ा । इसी प्रकार चार-पांच और राज्य हैं, जिनका डिस्कॉम्स का स्टेटस बहुत ही खराब है । वे डिटेल्स भी मेरे पास उपलब्ध हैं, लेकिन अगर मैं ज्यादा डिटेल्स बताऊंगा तो शायद कुछ सदस्यों को अच्छा नहीं लगेगा । मेरे पास हर राज्य के, कम्पनी-वाइज़, सलाना लॉस और एक्युम्युलेटेड लॉस, दोनों हैं । आप इसको जरा गम्भीरता से देखिए और अपने-अपने गिरेबान में देखकर बताइए कि क्या आपकी सरकार जनता के साथ न्याय कर रही है? जब आपको इतना लॉस होगा तो आप कोयले का पैसा नहीं दे पाएंगे । हक साहब, आपने बार-बार वैस्ट बंगाल की बात की । आपने हजारों करोड़ रूपए कोयले का भुगतान नहीं किया है, आपने जो बिजली खरीदी, उसका पैसा नहीं भरा है । जब वह स्थित बिगड़ जाएगी तो बिजली काटनी पड़ेगी या कोयले की सप्लाई बंद हो जाएगी, उस वक्त हाहाकार मच जाएगा । ...(**व्यवधान**)...

†Transliteration in Urdu script.

श्री सुखेन्दु शेखर राय (पश्चिमी बंगाल): एबन्डन्ड कोल माइन्स के कम्पनसेशन का क्या होगा? **...(व्यवधान)...**

श्री पीयूष गोयल: चलिए, आप यह एग्री करवा दीजिए, मैंने रिक्वेस्ट की थी, आप कोल रॉयल्टी और आपके ड्यूज को सेटऑफ करने की परमिशन हमें दे दीजिए, विषय खत्म हो जाएगा। **...(व्यवधान)...** इस तरह से मुझे लगता है कि अगर डिस्कॉम्स को **...(व्यवधान)...**

SHRI SUKHENDU SEKHAR ROY: Sir, he must say about compensation of abandoned coal mines. ...*(Interruptions)*...

श्री पीयूष गोयल: अगर हम इस प्रकार से डिस्कॉम को मजबूत करना चाहते हैं तो यह वास्तव में स्टेट का विषय है। स्टेट को मजबूती लाने में हमारी मदद करनी पड़ेगी। केंद्र की तरफ से, चाहे वह डिस्ट्रिब्यूशन नेटवर्क सुधारने के लिए पैसे की आवश्यकता हो, चाहे टेक्नोलॉजी की आवश्यकता हो, जो मदद आपको चाहिए, हम उसके लिए तैयार हैं। मैने पहले भी इस सदन में कहा था कि राज्य सरकारें एक कदम बढ़ें, केंद्र सरकार तीन कदम बढ़ने के लिए तैयार है। महोदय, कुछ राज्य ऐसे हैं जिन्होंने टैरिफ करेक्शन वर्षों तक नहीं किया है, उसकी वजह से भी लॉसेज बढ़ रहे हैं। मेरा मानना यह नहीं है कि आप सिर्फ टैरिफ बढ़ाकर ही लॉस कम कर सकते हैं। मैंने पब्लिकली कहा, वास्तव में अगर आप गुजरात में देखें तो गत 12 वर्षों में टैरिफ पूरे देश में सबसे कम वहां बढ़ा है, इस देश में मिनिमम परसेंटेज इंक्रीज टैरिफ की अगर कहीं हुई हैं, तो गुजरात में हुई है, जबकि इन्हीं 12 वर्षों में उनकी जनरेशन तीन गुना हो गयी। इन्हीं 12 वर्षों में उन्होंने हर घर को 24 घंटे बिजली दी, हर खेत को आठ-नौ घंटे बिजली दी, वहां हर उद्योग को बिजली मिलती है, उन्हें डीजी सेट नहीं लगाना पड़ता। इसके साथ-साथ उनका डिस्कॉम, जो 12 वर्ष पहले ढाई हजार करोड़ का लॉस करता था, वह आज पांच सौ करोड़ रूपए का प्रॉफिट करता है, वह भी पब्लिक सेक्टर में, कोई निजीकरण नहीं हुआ है। ये सरकारी अफसर वही अफसर हैं, जो अन्य राज्यों में काम करते हैं, जो केंद्र में काम करते हैं। **...(व्यवधान)...** इन्हीं अफसरों में, जब लीडरशिप अच्छी हो **...(व्यवधान)...**

SHRI P. BHATTACHARYA: Sir, there is a national organisation, NHPC. It is controlled by the Central Government. ...*(Interruptions)*... Hon. Minister didn't say a single word about NHPC. ...*(Interruptions)*...

THE VICE-CHAIRMAN (DR. SATYANARAYAN JATIYA): Please sit down. ...*(Interruptions)*... He is not yielding. ...*(Interruptions)*...

श्री पीयूष गोयल: जब प्रदेश की लीडरशिप अच्छी हो तो उस लीडरशिप से फायदा और नुकसान होता है, लीडरशिप से टर्न अराउंड होता है। **...(व्यवधान)...** This is not a subject of ownership; it is a subject of management. ...*(Interruptions)*... गुजरात ने यह मॉडल दिया कि मैनेजमेंट को सुधारा। अगर ऐसा करेंगे तो ओनरशिप अगर सरकारी भी होगी तब भी आप प्रॉफिट कर सकते हैं। वास्तव में अगर सभी स्टेट्स इस टाइप की लीडरशिप दे सकें, जिस प्रकार की हमने गुजरात में पायी, तो मुझे पूरा विश्वास है कि हर स्टेट का लॉस बंद हो सकता है, हर स्टेट का डिस्कॉम प्रॉफिट कर सकता है। महोदय, माननीय अच्युतन जी ने बताया था कि सरकार प्राइवेट सेक्टर्स को सभी डिस्कॉम्स देना चाहती है। मैं सम्माननीय सदस्य का ध्यान आकर्षित करूंगा कि सरकार की

तरफ से निजीकरण का कोई आदेश नहीं है, हमारा आदेश है, unbundling of discoms, जिसमें जनरेशन और डिस्ट्रीब्यूशन अलग-अलग होगा । It is called 'unbundling'. शायद हमारे समझाने में कभी कुछ गलती हुई हो । We have never talked of privatization, but of unbundling of discoms. श्री सी.पी. नारायणन जी ने निजी क्षेत्र में करप्शन और मिसमैनेजमेंट की बात की । निजी क्षेत्र को बुरा-भला कहना, it is a publicly accepted norm; it is a current coin. लोगों को भी अच्छा लगता है । ठीक है, करें, हम उसमें राजनीति कर सकते हैं, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि सरकारी क्षेत्र में भ्रष्टाचार नहीं है । ऐसा भी नहीं है कि निजी क्षेत्र में सब कुछ अच्छा है । Again, it is not private versus public; it is management, it is leadership. जब हमें इन्वेस्टमेंट ज्यादा चाहिए, तो हर क्षेत्र को प्रोत्साहित करना चाहिए, लेकिन अंकुश लाना चाहिए कि कोई बेईमानी न कर सके, वह काम हम सब का है । श्री राजीव गौडा जी ने बहुत अच्छे सुझाव दिए, मैंने उनके हर सुझाव को नोट किया है । उन्होंने बताया था कि effective metering हो real-time spark grids लगे, feeder separation हो । हां, उन्होंने यह बात कही कि feeder separation is not the only solution. हमने कभी भी यह नहीं कहा । हम तो कहते हैं कि हर स्टेट का solution उस राज्य में है । केंद्र कोई solution आपके ऊपर थोप नहीं रहा है । हर राज्य को calibrated solution निकालना पड़ेगा और हमारी सरकार उस solution को निकालने में आपकी मदद करेगी । हम कोई 'one size fits all' formula लेकर आपके पास नहीं आए हैं । मेरी समझ में feeder separation बहुत महत्वपूर्ण अंग है । उसके विषय में अगर कोई चाहे तो मैं चर्चा रखवा सकता हूं । आप सभी स्टेट्स के एमपीज आ सकते हैं । उसके लाभ आपको समझा सकता हूं । अगर आपका राज्य नहीं चाहे तो मत करिए, ऐसा कोई compulsion नहीं है । प्रफुल्ल पटेल ने काफी चीजें कही । T&D did not keep pace with generation. It is an absolutely correct assertion. हमने generation को देश में बढ़ाया, लेकिन forward and backward linkages पर ध्यान ही नहीं दिया, forward and backward linkage बना ही नहीं, backward linkage coal को अलग-अलग कारणों से फंसा के रखा। इसलिए न कोयला है, न evacuation capacity है, बीच में generation एक तरीके से अकेला खड़ा है । मेरी प्राथमिकता रहेगी और हमारी सरकार की प्राथमिकता रहेगी कि हम backward linkage और forward linkage पर फोकस करें । साथ ही साथ पर्याप्त मात्रा में generation भी बढ़े, लेकिन एक integrated and holistic planning हो जो तीनों अंगों को पूरे ध्यान से और correctly plan and growth पर development करें । Coal production and fuel supply, generation, transmission, distribution, metering, and, of course, collection of the bill हरेक पावर सेक्टर के पूरी chain को हमें address करना होगा । मेरे हाथ में उसमें बहुत कम है । अगर आप इस chain को ध्यान से देखें, Concurrent Subject होते हुए, इसमें ज्यादा काम स्टेट लेवल पर होगा । I can only be a facilitator. इसी प्रकार से high-capacity corridors देश भर में बनें । इन corridors के माध्यम से transmission capacity बढ़े और जो grid failure देश को 2012 में देखना पड़ा, जब कुछ राज्यों ने, मैं राज्यों का नाम नहीं लंगू, उनका आप सब को ध्यान होगा, कुछ राज्यों ने drawing of power इतनी बढ़ा दी, कुछ राज्यों ने तो 80 परसेंट तक drawing of power बढ़ाई थी जिसकी वजह से पूरे देश का गिर्ड collapse हुआ और अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में, अंतर्राष्ट्रीय arena में हमें एक तरीके से शर्मिंदगी देखनी पड़ी ।

एक ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर्स पर हमारी सरकार का विशेष ध्यान है । मुझे आपको बताते हुए खुशी है कि सरकार ने बड़े ambitious targets renewable energy के लिए हैं जिनके बारे में, मैं आपको

[श्री पीयूष गोयल]

बताऊंगा । साथ ही साथ उत्पादन के साथ ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर्स से वह evacuate होकर जनता तक पहुंच पाएं, उसके लिए हम इन्वेस्टमेंट भी करेंगे और उसको हम फोकस भी करेंगे । renewable energy production पर ध्यान तो हम दे ही रहे हैं, लेकिन energy storage एक नई चीज़ है जिस पर दुनिया में अभी रिसर्च हो रही है । हमारी सरकार ने storage के लिए चार पायलेट प्रोजेक्ट्स शुरू किए हैं । मुझे विश्वास है कि इन सब में से कैसे storage cost कम हो और हम रात को जो बिजली निर्माण होती है, उसको दिन में स्टोर कर पाएं और जो सौर रोशनी से सोलर एनर्जी दिन में निर्माण होती है, उसको स्टोर करके रात को दे पाएं । साथ ही साथ real-time grid monitoring और hundred per cent metering देशभर में consumption की हो, इस पर हमारा विशेष ध्यान है।

केरल के हमारे साथियों ने कुछ विषय बताए और समस्याएं बताईं । सम्मानीय श्री सी.पी. नारायणन जी ने transmission के बारे में भी बताया । मेरी दरख्वास्त है कि केरल और कर्णाटक दोनों राज्यों में transmission line लगाने के लिए हमें right of way की बड़ी समस्या है । अगर आप लोग हमारी मदद कर सकें, तो हम जल्द से जल्द वहां ट्रांसमिशन का जाल बिछा सकते हैं और आपके राज्य तक और ज्यादा बिजली पहुंचा सकते हैं ।

सर, वैसे तो समय कम है, लेकिन मेरे पास हरेक राज्य के पावर सेक्टर के हरेक विषय हैं, जो काफी सारे पेंडिंग हैं और जिनको राज्य सरकार से सपोर्ट चाहिए । हरेक राज्य के कोल के इतने सारे सब्जेक्ट्स मेरे पास हैं । मेरे पास Renewable Energy के सब्जेक्ट्स हैं, जरा spiral binding न करें तो सब्जेक्ट्स कम हैं । ये सभी राज्यों से संबंधित विषय हैं, अगर सभी राज्य हमारी मदद करें, तो मुझे पूरा विश्वास है कि हम इस पर बहुत तेजी से प्रगति कर पाएंगे । मैं 'Renewable Energy' के सब्जेक्ट पर आऊंगा, लेकिन मैं इससे पहले एक खुशखबरी देना चाहूंगा और इस पर मुझे पूरे सदन का समर्थन मिलेगा, ऐसा मुझे विश्वास है । इस देश के सामने एक बड़ी गंभीर समस्या है कि एक तरफ हम चाहते हैं कि सोलर एनर्जी ज्यादा से ज्यादा बने । इस विषय पर सदन के लगभग आठ-दस सदस्यों ने मेरा ध्यान आकर्षित किया है । दूसरी तरफ देश में जो domestic manufacturers हैं, जो local manufacturers हैं, उनकी ओर किसी ने ध्यान ही नहीं दिया है । उनकी competitiveness कम है । पहले समय में taxation structure थोड़ा lopsided था, तो imported plant duty-free था और लोकल प्रोडक्शन पर taxes और duties लगते थे, तो लोकल तो कभी competitive हो ही नहीं सकता है । ऐसी परिस्थित में उनको सरकार के सामने कुछ केसेज वगैरह करने पड़े । मैंने कल जब सबकी भावनाएं सुनीं और आपको याद होगा कि कल स्वदेशी का विषय भी उठा था । मेरे ऊपर टिप्पणी भी हुई कि मैं स्वदेशी जागरण मंच से हूं । मैं बहुत गर्व से कहता हूं कि मैं स्वदेशी में विश्वास करता हूं और यह सरकार स्वदेशी में विश्वास करती है । We want to see a self-reliant, independent and strong domestic manufacturing capacity in this country. ...(*Interruptions*)... इसीलिए इस सरकार ने एक निर्णय किया कि हम स्वदेशी solar manufacturers को प्रोत्साहित करने के लिए डिफेंस में जो बिजली की युटिलाइजेशन होती है, कंजम्पशन होती है, उसके लिए देश में एक हजार मैगावाट के solar power plants लगाएं और वो tender का condition होगा कि उसमें सिर्फ भारतीय कम्पनी, local, domestic manufacturing companies हजार मेगावाट टेंडर्स में भाग ले पाएंगी ।

इसी श्रृंखला में मैं चाहता हूं कि डोमेस्टिक प्रोडक्शन बढ़े । आज उन सबकी हालत खराब है और आधे बीमार पड़े हैं, क्योंकि उनका competitiveness नहीं है । उनको competitive बनाना

होगा, ताकि उनको दिखे कि आगे आने वाले दिनों में सरकार डोमेस्टिक इंडस्ट्री को सपोर्ट करेगी । इसीलिए हमने कुछ सरकारी क्षेत्र की पावर कम्पनीज़ को अपने 'Renewable Power Obligation' को, जिसको मैं और सख्त करने जा रहा हूं, फुलफिल करने के लिए एक हजार मेगावाट इसी वर्ष में domestically manufactured solar plants हमारे सरकारी क्षेत्र में लगेंगे । इसी वर्ष उसके टेंडर्स निकलेंगे और उसमें भी सिर्फ domestic companies भाग ले पाएंगी । आगे आने वाले दिनों में जैसे-जैसे उनकी performance और capacity बढ़ेगी, सरकारी कम्पनियां जो domestic solar cells, modules, glass बनाते हैं, उनको सपोर्ट करने के लिए, यह WTO-compliant स्कीम है, जिस पर मैंने अच्छे तरीके अध्ययन किया है, ताकि कल को कोई मेरी सहयोगी निर्मला जी को या कल आनन्द जी को ज्यादा तकलीफ न हो । हमने complaint scheme भारत के उद्योगों को, भारत की प्रोडक्शन क्षमता को बढ़ाने के लिए तय की है कि हजार मेगावाट डिफेंस में और हजार मेगावाट सरकारी कम्पनी, डिफेंस की तो पांच वर्षों की अवधि में, सरकारी कम्पनियां इस वर्ष के अंदर और आगे आने वाले वर्षों में इससे भी तेज गति से domestic manufacturers से खरीदेंगे । मुझे लगता है कि यह देशहित में एक रेवोल्यूशनरी स्टेप होगा और विश्वास है कि सदन इस पर समर्थन भी देगा । इसी प्रकार से renewable energy, जो environment friendly है, पर्यावरण के लिए अच्छी है, उसको तेजी से प्रोत्साहन देने के लिए हमने NCEF (National Clean Energy Fund) में जो पचास रुपये प्रति टन सैस लगता था, उसको इस बजट में डबल करके सौ रुपये प्रति टन कर दिया है । हमारी सरकार उस पैसे को वास्तव में प्रोजेक्ट्स तक पहुंचाएगी । कई सम्माननीय सदस्यों ने कहा है कि आप NCEF से पैसा दीजिए, यह कीजिए, वह कीजिए, लेकिन दुर्भाग्य से स्थिति ऐसी है कि जब मैंने मंत्रालय का भार संभाला तो मुझे शुरू में किसी ने बताया कि NCEF में 12-13 हजार करोड़ रुपये हैं, लेकिन जब वास्तव में देखा तो पता चला कि मात्र 500 करोड़ रुपये renewable energy पर खर्च हुए, बाकी पैसा फिस्कल डेफिसिट भरने में चला गया । गत तीन वर्षों में NCEF में renewable energy के लिए जो पैसा आना था, वह चला गया और हमारे renewable energy क्षेत्र को सिर्फ 500 करोड़ मिले । पर हम उस परिस्थित को बदलेंगे तथा renewable energy में और ज्यादा पैसा लगे, इस पर ज्यादा ध्यान देंगे । जब मैंने भार संभाला तो मुझे 2000 करोड़ की ओल्ड और 1000 करोड़ की नई, यानी 3000 करोड़ रुपये की पुरानी पेंडिंग सब्सिडीज़ मिलीं । हमने उनमें से 460 करोड़ की ऑलरेडी क्लियर कर दी हैं एवं 800 करोड़ की अगले तीन महीने में क्लियर करेंगे । मैं कोशिश करूंगा कि इस वर्ष के आखिर तक गत वर्ष की जितनी सब्सिडीज़ हैं, उनको क्लियर करने का कोई साधन जुटाऊं ।

मुझे यह बताते हुए बहुत प्रसन्नता हो रही है कि वित्त मंत्री जी ने Mega Solar Parks की घोषणा की है। भविष्य में, इस देश में जल्द ही बड़े पैमाने पर सौर ऊर्जा बने, हम इसके लिए चार-पांच अलग-अलग राज्यों में सोलर एनर्जी पार्क्स एनाउंस करेंगे । मेरे पास कुछ राज्यों के नाम ऑलरेडी आ चुके हैं । जैसे आंध्र प्रदेश ने सबसे पहले जमीन दी है, जिसमें 1000 मेगावाट का Mega Solar Park आ सकता है । कुछ और राज्यों से भी बातचीत चल रही है । यदि और कोई राज्य जमीन दे सके तो हम उसमें और ज्यादा तेजी से सौर ऊर्जा लगाएंगे, उसको सपोर्ट करेंगे । आपके राज्य को बिना कोई नुकसान उठाए और ज्यादा बिजली मिले, हमने इसके लिए भी एक योजना बनाई है । मेरे पास उस हर सदस्य का नाम है, जिसने जो विषय उठाया है । जैसे domestic production का मुद्दा श्री रंगराजन जी ने, कानीमोझी जी ने उठाया था । इस पर श्री नाच्चीयप्पन जी ने भी बात की थी, पर मैं अभी एक-एक सदस्य का नाम नहीं ले रहा हूं । **...(व्यवधान)...**

प्रो. राम गोपाल यादव: क्या यह आखिरी पन्ना है?

उपसभाध्यक्ष (डा. सत्यनारायण जटिया): सदन ने इजाजत दी है तो होगा ।

श्री पीयूष गोयल: मेरे ख्याल से street lights, solar rooof tops आदि विषयों में भी बहुत संभावना है, जिससे देश में सूर्य से उत्पादित होने वाली बिजली बढ़ेगी । हमने बजट में कुछ स्कीम्स ऑलरेडी एनाउंस की हैं । हम दिल्ली को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लेकर कोशिश कर रहे हैं कि देश भर में, particularly urban centers में कैसे सोलर पावर यूज करके इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई बढ़ाएं । Wind में wind energy, जोकि दो साल से ठप्प पड़ी थी, क्योंकि accelerated depreciation दो वर्ष पूर्व अचानक विदड्रा कर दिया गया था, इस बजट में उसको रिइंट्रोड्यूस किया गया है । मैं समझता हूं कि आने वाले दिनों में wind energy भी इस देश में पर्याप्त और बड़े स्वरूप में बिजली का उत्पादन करेगी ।

हमने net metering पर भी ध्यान दिया है । सम्मानीय सदस्य श्री सी.पी. नारायणन जी ने मेरा ध्यान आकर्षित किया है । तीन प्रदेशों में net metering ऑलरेडी चालू है, उसके रूल्स भी बने हैं । मैं चाहूंगा कि सभी स्टेट्स net metering में सूर्य रोशनी, जो बिल्डिंग में बनती है, उसका जो सरप्लस है, जिसको फिर से ग्रिड में डाला जाता है, जिसका क्रेडिट प्रोड्यूसर या घर के मालिक को मिलता है, It is a win-win situation for both, जिसमें प्रदेश को बिजली भी मिलती है और प्रोड्यूसर को अपना बिजली का बिल कम करने का साधन भी मिलता है । इसी प्रकार से जो दूर-दूर के छोटे-छोटे इलाके हैं, hamlets हैं, ट्राइबल एरियाज है, वहां पर off-grid solutions की स्कीम्स भी हमारा मंत्रालय बनाने में लगा हुआ है । वी.पी. सिंह बदनौर जी ने गार्बेज से उत्पादित की गई बिजली का जिक्र किया था । कल ही देश भर से 150 सायंटिस्ट्स, जिनमें डा. चिदंबरम, जो भारत सरकार के सायंटिफिक एडवाइजर हैं, वे भी आए थे । दो दिनों में उन लोगों ने बताया कि नए-नए प्रयोगों के ऊपर रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो । हमारी सरकार ने रिसर्च एंड डेवलपमेंट को प्राथमिकता देना तय किया है । हम और ज्यादा नई टेक्नोलॉजी का निर्माण करना चाहते हैं, जिससे रिन्युएबल एनर्जी की एफिशिएंसी और आउटपुट बढ़ सकती है । अनु आगा जी ने भी कहा था कि इंडिया सेंट्रिक रिसर्च होनी चाहिए । हम टेक्नोलॉजी के लिए कब तक अमेरिका और यूरोप के ऊपर डिपेंडेंट रहेंगे? मैं सदन को विश्वास दिलाता हूँ कि भारत में अच्छी क्वालिटी की रिसर्च हो, इसके लिए मैंने कल सायंटिस्ट्स को आश्वासन दिया है कि बिना बजट की चिन्ता किए, आपको जो इक्विपमेंट चाहिए, आपको जो साधन चाहिए, हमारी सरकार देने के लिए तैयार है, आप भारत में रिसर्च करिए । ...**(व्यवधान)**... अब ज्यादा प्वाइंट्स नहीं है, मैं जल्दी से खत्म कर रहा हूँ ।

सीएसआर के बारे में मेरे पास बहुत सारी चीजें हैं । I have with me all these files and books. लेकिन मेरे माइंड में आज ही बैठे-बैठे ध्यान आया कि जो-जो राज्य हमें इन समस्याओं को सुलझाने में मदद करेंगे, हम उनमें सीएसआर का फोकस भी बढाएँगें । जहां-जहां पर कोयले की खानें जल्दी खुलती हैं, जहां-जहां पर लैंड एक्वायर करके आप हमें ट्रांसमिशन लाइन बनाने देते हैं, जहां-जहां आप टीएंडडी लॉसेज, थेफ्ट को कम करते हैं, मैं समझता हूँ कि हमारे जो उपक्रम हैं, उनके सीएसआर का बजट वहां ज्यादा लगे । मुझे अपने वेस्ट बंगाल के साथी को बताते हुए बड़ी खुशी है कि आज ही मेरे सज्ञां में लाया गया कि तीन वर्ष पहले कोलकाता में एक कैंसर हॉस्पिटल के लिए कोल इंडिया लिमिटेड ने कुछ कमिटमेंट्स की थी, लेकिन उसने तीन वर्ष में उनको पूरा नहीं किया । मैंने आज ही कोल इंडिया लिमिटेड को निर्देश दिया है कि जो-जो कमिटमेंट्स तीन वर्ष पहले की गई थीं, वे

सब 15 दिन के अन्दर पूरी की जाएँ । कोलकाता में टाटा का जो कैंसर हॉस्पिटल है, उसको ईस्टर्न इंडिया में कैंसर पेशेंट्स की वेलफेयर के लिए तेजी से काम करना है । **...(व्यवधान)...**

(MR. DEPUTY CHAIRMAN *in the Chair.*)

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Mr. Minister, please shorten your speech.

श्री पीयूष गोयल: सर, हाइडल एनर्जी में जो पोटेंशियल है, वह वास्तव में इस देश के लिए बहुत अच्छा है । आपको पता है कि भागड़ा-नांगल परियोंजना, जिसे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने उस समय लगाया था, उसकी बिजली आज भी 96 पैसे में मिलती है । क्यों न पूरे देश में हाइडल एनर्जी के पोटेंशियल को और तेजी से इम्प्लीमेंट किया जाए । **...(व्यवधान)...**

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Mr. Minister, address the Chair.

श्री पीयूष गोयल: मैं इसके लिए सभी राज्यों से दरख्वास्त करूँगा । जैसे सुबानसिरी में 6,000 करोड़ रूपए लग चुके हैं । इसमें असम के मित्रों को कुछ आशंकाएँ हैं । मैं अगले महीने एक मीटिंग बुला रहा हूं, जिसमें असम के मित्रों की जो आशंकाएँ हैं, उनको दूर करने की कोशिश की जाएगी । मैं समझता हूँ कि इसी क्रम में देश भर में जितने हाइडल प्रोजेक्ट्स फँसे हैं, हम उनको जल्द-से-जल्द कार्यान्वित करें और उनको शुरू करें । हम इस दिशा में लगेंगे ।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please conclude. I think it has been more than one and a half hours ...(*Interruptions*)... Please conclude. ...(*Interruptions*)... You can send rest of the points in writing to the hon. Members who raised them. ...(*Interruptions*)...

SHRI PIYUSH GOYAL: Sir, it is my earnest belief that we need to have transformative changes in the policy ...(*Interruptions*)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: He is not yielding. ...(*Interruptions*)... You sit down. ...(*Interruptions*)...

SHRI PIYUSH GOYAL: Sir, unless we do transformative changes, the situation cannot be improved. I think our Government is committed to implementing transformative changes and not incremental changes. We will enforce renewable power obligations sincerely. We will quickly get the new UMPPs into operation. We will quickly bid for more UMPPs so that more power generation capacity can be set up. We will make an effort to take up more and more coal blocks so that coal production can be taken up. ...(*Interruptions*)... I believe the Electricity Act, 2003, which Shri Atal Bihari Vajpayee's Government had brought in 2003, was a revolutionary path. But eleven years have passed and I think it needs a re-look. It needs to be more contemporary. It needs to address the challenges of 2014 and beyond, and in the next session, we shall bring out the changes in tariff policy in electricity regulation, which will prepare India to meet the challenges of the power sector for the next 10 years, 20 years and beyond. I would seek the support of the entire House, not to politicise, when those amendments come in, the improvements in the power sector, but to look for the interest of the nation. ...(*Interruptions*)...

[Shri Piyush Goyal]

Sir, I must here mention that I am getting a tremendous support from several State Governments, from several Ministers in my Government, and we are working in a seamless fashion to address all the issues before different Ministries. Whenever we have a problem, Sir, it is flagged off not through paperwork but through action. This Government of Shri Narendra Modi, instead of focussing only on new laws and new Acts, is actually focussing on action, and what we are doing in this sector is action. I have a few more plans to announce to you, but it looks like there is a paucity of time. But there are issues relating to the Railways where I need your support. I need your support to sort out issues in Jharkhand and Odisha. If two rail links in Jharkhand and Odisha, which Prafulbhai mentioned, are sorted out and some land acquisition and forest clearance is locally cleared, we can transport nearly 100 million tonnes every year. Look at the relief it will give to India. If we can sort out forest clearances or the land acquisition matters at the State level quickly, we can quickly transmit power to remote areas in the South and in the North-East. Please give us your support. Please work in partnership with the Government and I can assure you that in a transparent rule base and incentivising good performance, this Government will take forward the agenda of 24X7 power to all the homes and to every person in this country. I can assure you that this Government and the three Ministries are committed to fulfilling the vision of Shri Narendra Modi and I will look forward to your support in the days to come. Thank you.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Thank you very much. ...(*Interruptions*)... Why are all of you standing ? What is the point? ...(*Interruptions*)...

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री (श्री थावर चन्द गहलोत): क्लैरिफिकेशन के बाद एक घंटा और लगेगा । जब इन्होंने इतने विस्तार से जवाब दे दिया है, इसके बाद अब क्लैरिफिकेशन की कोई आवश्यकता नहीं है ।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Okay. ...(*Interruptions*)... No clarifications. ...(*Interruptions*)... All of you are standing. What can I do? ...(*Interruptions*)... What is the point ? ...(*Interruptions*)... Mr. Karimpuri, what is the point ? ...(*Interruptions*)... I will call you. Now, I call Mr. Karimpuri. What is your point?

श्री थावर चन्द गहलोत: वे अपनी बात लिखित में दे दे, उनका लिखित में जवाब आ जाएगा ।

श्री अवतार सिंह करीमपुरी (उत्तर प्रदेश): सर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से एक क्लैरिफिकेशन चाहता हूं । अभी वे क्लैरिफाई क्या करेंगे, वे तो सेलिब्रेशन में लगे हुए हैं ।

महोदय, मैं उनसे यह क्लैरिफिकेशन चाहता हूं, डिस्कशन में हमने जो कहा था कि पावर डिपार्टमेंट में **...(व्यवधान)...** ऑनरेबल मिनिस्टर साहब **...(व्यवधान)...** सर, आप इनका ध्यान तो इस ओर दिलाइए । **...(व्यवधान)...**

MR. DEPUTY CHAIRMAN: What is this happening? Mr. Ramakrishna, you are having your back towards the Chair and standing! What is this happening? I am sorry. ...(*Interruptions*)... Mr. Minister, he is seeking a clarification. Please listen to him. ...(*Interruptions*)...

SHRI PIYUSH GOYAL: Sir, I am happy to clarify anything. ...(*Interruptions*)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Okay. Just put your query. There is no time. Just ask your question.

श्री अवतार सिंह करीमपुरी: सर, मैं यह जानना चाहता हूँ, मैंने कल मिनिस्टर साहब से यह क्लेरिफिकेशन चाहा था कि जो पॉवर डिपार्टमेंट में एससी, एसटी, ओबीसी के रिप्रेजेंटेशन के मामले में बहुत बड़े पैमाने पर बैकलॉग पड़ा है। उस बैकलॉग को कम्प्लीट करने के लिए मंत्री जी क्या निर्णय लेंगे? दूसरा, **...(व्यवधान)...**

MR. DEPUTY CHAIRMAN: No, no. ...(*Interruptions*)... Now, Shri P. Bhattacharya. ...(*Interruptions*)...

श्री अवतार सिंह करीमपुरी: सर, इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था, एक टीवी चैनल पर स्टोरी चली थी कि कोयले की कमी के कारण एनटीपीसी के छः प्लांट्स बंद हो जाएँगे। उसके बारे में और जो एससी, एसटी, ओबीसी का बैकलॉग पड़ा है, उसके बारे में भी ये जानकारी दें। **...(व्यवधान)...**

SHRI P. BHATTACHARYA : Today, I have seen in the media that the Prime Minister will visit Jammu and Kashmir State. It is very good. I was also told that he will inaugurate two power plants - one at Kargil and the other at Leh . These power plants are already in operation for the last 2 years. Again these will be opened. When these plants are already in operation, how many times they will be inaugurated ?

SHRI KALPATARU DAS (Odisha) : Mr. Deputy Chairman, Sir, the hon.Minister during his reply has repeatedly sought the support of the State. He has also mentioned the name of the Chief Minister of Odisha, and has also complimented him.

Odisha is having 25 per cent.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Put the question.

SHRI KALPATARU DAS: Odisha is having 25 per cent of coal deposits. Is the Government of India going to provide free thermal power at the rate of 30 per cent as in the case of hydro-power to the Odisha State? Because the State is bearing all the pollution, acquiring land under Land Acquisition Act. The State is suffering.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Okay, you have put your question.

SHRI KALPATARU DAS: Second point is, they are importing coal from outside. The NTPC is having a plant at Talcher and Kania. Now, the Government of India has invited bid for the supply of coal to the NTPC.

डा. अनिल कुमार साहनी (बिहार): मेरा यह सवाल है कि एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटी का जो बैकलॉग है, उसको कब तक भरा जाएगा, क्योंकि आपके हर विभाग में हर जगह पर बैकलॉग है तथा कोई भी 27 परसेंट को फुलफिल नहीं कर रहा है । आप इसको देखिए ।

दूसरा, मैंने मुजफ्फरपुर के बारे में, वहां के पर्यावरण के सम्बन्ध में कहा था कि वहां पर पर्यावरण प्रदूषण के कारण बहुत सी परेशानियां हो रही हैं । वहां लीची की बरबादी हो रही है । उस पर भी कोई शब्द नहीं बोला गया । उसके कारण वहां के बहुत सारे मछुआरों को भी समस्या हो गई है । उस पर भी कुछ नहीं बोला गया । तो इस पर क्लेरिफिकेशन दीजिए, ताकि उन लोगों को भी संतुष्टि हो सके कि आपके द्वारा कार्य किया जा रहा है । **...(व्यवधान)...**

SHRI SUKHENDU SEKHAR ROY: Very recently the NTPC authorities have pressed the panic button that the NTPC was having coal stocks only for 2-3 hours ..(*Interruptions*).. Please allow me to speak. You don't have the patience. I did not speak since morning. I was only listening to everyone.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please continue.

SHRI SUKHENDU SEKHAR ROY: The NTPC authorities have sent a letter to the Government stating — as it is reported in the press also — that they don't have coal stocks even for 2-3 hours. Subsequently the Coal India Ltd., has clarified that whatever the requirement of the NTPC plants, that they have supplied, and all the NTPC plants are having 100 per cent coal stocks. Then, why did the NTPC press the panic button ?

SHRIMATI VIJILA SATHYANANTH (Tamil Nadu): Mr. Deputy Chairman, Sir, I want to know from the Minister of Power whether 10 per cent unallocated share, 15 per cent from Neyveli Lignite Corporation and from Kudankulam Nuclear Power Plant will be allocated to Tamil Nadu. Will the Central Government allocate 15 per cent additional power to Tamil Nadu?

DR. T. SUBBARAMI REDDY (Andhra Pradesh): Sir, I congratulate the Minister of Power, Mr. Piyush Goyal.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: No. Put the question. There is no time for that.

DR. T. SUBBARAMI REDDY: Before putting the question, I want to say that he is a dynamic person. Now, I am putting an important question. If he can't reply now, he can send it to me in writing. The Coal Linkage Committee says, you must have the PPA only then will you get coal linkage. Just now the Minister said that the State Governments are not calling the bids. If they don't call bids, then, the PPA does not come. If the Coal India Ltd does not supply, how will the project come up? Previously nobody could resolve it. Now it is your chance to become a heroic personality. Please go into it and then give the reply.

श्री रामदास अठावले (महाराष्ट्र): सर, महाराष्ट्र के रत्नगिरी जिले में एक चैतापुर न्युक्लीयर

पॉवर प्रोजेक्ट है, वहां पर इसको लेकर लोगों का काफी विरोध हो रहा है । अमेरिका और दूसरे देशों में न्यूक्लीयर पॉवर प्रोजेक्ट्स से बहुत लोगों की डेथ होती है । मंत्री महोदय भी महाराष्ट्र के हैं, उनसे मेरा निवेदन यह है कि यह सही है कि आज पॉवर की आवश्यकता है, इसके लिए आपको अभी पॉवर मिली है और इस पॉवर को बढ़ाने के लिए भी हमें काम करना है, लेकिन लोगों की डेथ न हो, इसके लिए जैतापुर प्रोजेक्ट को जो मंजूरी मिली है, उसको समाप्त करने की आवश्यकता है । इसके स्थान पर दूसरे माध्यम से यानी कोयला, सोलर या पानी से पॉवर जनरेशन को ज्यादा बढ़ाने की आवश्यकता है । इसके लिए आपको विचार करना चाहिए और जैतापुर प्रोजेक्ट को बंद करना चाहिए ।

श्री नरेंद्र बुढानियाः सर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री के ध्यान में यह बात लाना चाहता हूँ कि सौर ऊर्जा के क्षेत्र में राजस्थान में बहुत संभावनाएं हैं और इन्होंने अभी सदन को अवगत कराया कि हम कुछ स्टेट्स में सौर ऊर्जा पार्क बनाने जा रहे हैं । राजस्थान एक पिछड़ा हुआ प्रदेश है और क्षेत्रफल में वह बहुत फैला हुआ है । मैं यह जानना चाहता हूँ कि आप जो सौर ऊर्जा पार्क बनाने की बात कर रहे हैं, क्या उसमें राजस्थान को शामिल करने का प्रस्ताव है या नहीं है?

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूँ कि मैंने सदन में यह बात रखी थी कि गुजरात की बात बहुत की जा रही है, मंत्री जी गुजरात से बहुत खुश हैं, हम भी खुश हैं, लेकिन गुजरात के अंदर 2007 और 2009 में Vibrant Summit हुआ, उसके अंदर एनर्जी सेक्टर में 4 लाख 53 हजार करोड़ रूपए के निवेश के लिए एग्रीमेंट्स हुए, लेकिन उसमें से सिर्फ ड़ेढ परसेंट खर्च हुआ है और जितने एमओयूज हुए, उनमें से सिर्फ तीन ही ऑपरेशनल हैं । जब गुजरात की इतनी बात की जा रही है, वहां इतने पैसे के एमओयूज हुए, तो वे क्यों पूरे नहीं हुए?

श्री मोहम्मद शफी (जम्मू और कश्मीर): महोदय, मैं आपकी वसातत से ऑनरेबल पॉवर मिनिस्टर से यह जानना चाहता हूँ कि रियासत जम्मू-कश्मीर का एक मामला पॉवर के हवाले से मरकज़ी हुकूमत के पास पड़ा हुआ है । बुट स्कीम के तहत सलाल पॉवर प्रोजेक्ट जिसको एनएचपीसी चला रहा है, उसने इसको बिल्ट किया, चलाया और उसने उससे अपनी सारी रकम वसूल भी कर ली, अब उसको स्टेट गवर्नमेंट को ट्रांसफर किया जाना है । यह मामला कई सालों से लटका हुआ है । मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या वे इस पर गौर करते हुए इस पॉवर प्रोजेक्ट को स्टेट गवर्नमेंट को ट्रांसफर करेंगे या नहीं करेंगे?

सर, मैं एक और सवाल पूछना चाहता हूँ और वह यह है कि यहां पर गुजिश्ता तीन साल पहले 2010 के एजिटेशन के बाद एक रंगराजन कमिटी बनी । उसने रियासत की माली सूरतेहाल को बेहतर बनाने के लिए कई और सिफारिशात कीं, उनमें एक सिफारिश यह भी थी कि रियासत जम्मू-कश्मीर में जो पॉवर प्रोजेक्ट्स बनें है, जिनको एनएचपीसी चलाती है, जैसे उरी-1 है, डुलहस्ती है, इन पॉवर प्रोजेक्ट्स को स्टेट गवर्नमेंट को ट्रांसफर करना चाहिए । अभी तक इन सिफरिशात पर अमल आवरी नहीं हुई । सर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि अगर एक हाई पॉवर कमिटी ने ये सिफारिशात की हैं, तो क्या वे उन पॉवर प्रोजेक्ट्स को रियासत जम्मू-कश्मीर की सरकार को ट्रांसफर करेंगे या नहीं करेंगे, क्योंकि यह रियासत जम्मू-कश्मीर की अवाम में एक बड़ी नाइंसाफी मानी जा रही है कि हमारे पानी की दौलत से पॉवर तो बन रहा है, लेकिन हमें सिर्फ 12 परसेंट पॉवर रॉयल्टी के तौर पर मिलती है, बाकी पॉवर जो इस्तेमाल की जाती है, उसका कोई फायदा रियासत को नहीं मिलता है? इस इस्तेहसाल को खत्म करना बहुत जरूरी है ।

† **جناب محمد شفیع :** مہودے، میں آپ کی وساطت آنریبل پاور منسٹر سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ ریاست جموں کشمیر کا ایک معاملہ پاور کے حوالے سے مرکزی حکومت کے پاس پڑا ہوا ہے۔ بوٹ اسکیم کے تحت سلال پاور پروجیکٹ جس کو این۔ایچ۔پی۔سی۔ چلا رہا ہے، اس نے اس کو بلٹ کیا، چلایا اور اس نے اس سے اپنی ساری رقم وصول بھی کر لی، اب اس کو اسٹیٹ گوورنمینٹ کو ٹرانسفر کیا جانا ہے۔ یہ معاملہ کئی سالوں سے لٹکا ہوا ہے۔ میں یہ جاننا چاہتا ہوں گا کہ کیا وہ اس پر غور کرتے ہوئے اس پاور پروجیکٹ کو اسٹیٹ گوورنمینٹ کو ٹرانسفر کریں گے یا نہیں کریں گے؟

سر، میں ایک اور سوال پوچھنا چاہتا ہوں اور وہ یہ ہے کہ یہاں پر گزشتہ تین سال پہلے 2010 کے ایجیٹیشن کے بعد ایک رنگ راجن کمیٹی بنی۔ اس نے ریاست کی مالی صورتحال کو بہتر بنانے کے لئے کئی اور سفارشات کیں، ان میں ایک سفارش یہ بھی تھی کہ ریاست جموں کشمیر میں جو پاور پروجیکٹس بنے ہیں، جن کو این۔ایچ۔پی۔سی۔ چلاتی ہے، جسے اری۔ا ہے، ڈل۔ہستی ہے، ان پاور پروجیکٹس کو اسٹیٹ گوورنمینٹ کو ٹرانسفر کرنا چاہئے۔ ابھی تک ان سفارشات پر عمل آوری نہیں ہوئی۔

سر، میں آپ کے مادھیم سے مانّئے منتری مہودے سے جاننا چاہوں گا کہ اگر ایک ہائی پاور کمیٹی نے یہ سفارشات کی ہیں، تو کیا وہ ان پاور پروجیکٹس کو ریاست جموں کشمیر کی سرکار کو ٹرانسفر کریں گے یانہیں کریں گے، کیوں کہ یہ ریاست جموں کشمیر کی عوام میں ایک بڑی ناانصافی مانی جا رہی ہے کہ ہمارے پانی کی دولت سے پاور تو بن رہا ہے، لیکن ہمیں صرف 12 فیصد رائلٹی کے طور پر ملتی ہے، باقی پاور جو استعمال کی جاتی ہے، اس کا کوئی فائدہ ریاست کو نہیں ملتا ہے؟ اس استحصال کو ختم کرنا بہت ضروری ہے۔

SHRI A.V. SWAMY (Odisha): Sir, I was greatly inspired by the manner in which our young Minister was answering...

†Transliteration in Urdu script.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Then don't trouble him with more questions.

SHRI A.V. SWAMY: I am talking of something which nobody must have thought of. He is using non-replenishable resources. We are digging up the earth, emptying it, and whatever resoures are there, these will be over very soon. Coal, for instance...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please put your question.

SHRI A.V. SWAMY: I would like to know whether the Ministry has calculated how much resources they have now to meet the increasing demand of power. Alternatively, whatever he is suggesting about renewable energy, that is, 1,000 MW, is just peanuts compared to the rate at which they are using nonreplenishable resources. I thought that this must be given due attention. Otherwise, we will be recorded in history as thieves of the country's resources of future generations.

श्री रामनारायण डूडी (राजस्थान): उपसभापति महोदय, मैं सम्माननीय मंत्री जी से यह निवेदन करना चाहता हूँ कि राजस्थान के अंदर सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा, दोनों सबसे ज्यादा हैं । उस हिसाब से क्या आप सौर ऊर्जा और विंड पावर के लिए राजस्थान को एक हब के रूप में बनाना चाहते हैं, क्योंकि वहां जमीन भी उपलब्ध है और इन दोनों के लिए जिन चीजों की जरूरत पड़ती है, वे सारी की सारी राजस्थान में उपलब्ध हैं । मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या सरकार यह विचार रखती है?

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Mr. Minister, if you want, you can reply now. Or else, you can write to them. It is up to you.

SHRI PIYUSH GOYAL: Sir, Members should go back satisfied. I have many more things which I wanted to say.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now, you only reply to these Members' queries. You do not have to say anything more.

SHRI PIYUSH GOYAL: Sir, first of all, I have categorically stated in this august House about the six plants of NTPC. I have the letter which the Press did not, I think, understand, and another colleague here mentioned about the controversy between the NTPC and the Coal India. This, I thought, I would address in my reply, but I will mention it now. The story is as follows. The NTPC requires a certain amount of coal and it has a certain annual contracted quantity of coal that it will get every year. In this year also, the Coal India has supplied adequate quantity as per the requirement. So, if you see Singrauli, they have already dispatched 104 per cent of the coal required from 1st July to 15th July. In the case of Rihand, 102 per cent; Vindyachal, 100 per cent; Sipat, 85 per cent; Ramagundam, 100 per cent; and Simhadri, 112 per cent. Now these are the six NTPC plants, which were amongst the list of critical stock of less than four days. Because of the hydel problem, — hydel energy went down as there was delayed

6.00 P.M.

[Shri Piyush Goyal]

monsoon, which you are all aware of — would you have preferred that the NTPC keep their stock in their godowns, not produce extra power and let the people suffer because hydel power has come down due to natural reasons? Instead of that, I told my officers, "Produce more electricity. Let the people not suffer." Therefore, the coal generation in June was 20 per cent more than the corresponding period last year. And that is how we have been able to satisfy the people's needs. So, there was no contradiction. But it needed a little understanding. To understand this, I thought I would explain it in the House. If anybody wants, there is an internal correspondence of the Coal India to the NTPC which describes what the materialization was. Materialisation means the amount received against the contracted quantity. Now if that quantity has come down, it is because of higher generation. So, the NTPC is right when they said that they have a shortage because they want more, and यह दिल मांगे मोर, परन्तु यह उनके पास आया है और उन्होंने इसका इस्तेमाल किया है । Similarly, I would like to tell Sukhenduji that in respect of those 23 power plants, which have lower stocks, we are addressing that issue, and we are trying to ensure that nobody has a shortage. But in a country where 20 per cent growth which is unprecedented...

श्री राजीव शुक्ल (महाराष्ट्र): डिप्टी चेयरमैन सर, छः बज गए हैं । **...(व्यवधान)...** यह खत्म कर लें इसके बाद एडजॉर्न करिए ।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: What is your problem? ...(*Interruptions*)...

डा. अनिल कुमार साहनी : पहले भी 12 बजे रात तक हाउस चला था । **...(व्यवधान)...**

SHRI PIYUSH GOYAL: Sir, hon. Member, Shri Bhattacharya, raised an issue about the hon. Prime Minister dedicating to the nation two hydel plants. His party has been in Government for many years. He is a very, very senior Member. I respect him and his age. But I am sure he is aware that the process of dedicating a project to the nation is different from commissioning. The projects have certainly been commissioned, but they are not yet dedicated to the nation. The programme for which the hon. Prime Minister is going is to dedicate these plants to the nation which is the due process of completing any project. Sir, there was a talk about giving 30 per cent power to Odisha which hon. Member Kalpataru Dasji raised. There is a Gadgil formula. I have already mentioned that. If the House, the Members of Lok Sabha and Rajya Sabha, agree and all States agree not to fight, I am happy to re-open the Gadgil formula.

Sir, Mr. Sahani raised a very important issue of Muzaffarpur. I thought I had addressed it first when I started. Sir, that plant was set up in 1984, which is more than 25 years old and therefore, it is having a continuous problem of inefficiency and polluting

the environment in your beautiful State. Therefore, we came out with this policy. It can now be replaced by a super critical thermal plant, most modern technology which is environment friendly. We will help to do that, and I will instruct NTPC to take up that project on high priority, if it is NTPC. I don't know if it is NTPC or your State Government.

Sir, Vijila*ji* raised the issue of unallocated power in Neyveli and Kudankulam. Sir, unallocated power is given to States where the problem of deficiency is high and I am happy to tell you, Madam, that Tamil Nadu is amongst the better performing States today. You are actually not a power deficient State, and, therefore, that unallocated power has to be given to the States which are more in need of it, and I hope you will never need unallocated power. But I must still mention that from the Southern grid, whatever is the unallocated power, more than 25 per cent of that still comes to your State and Tamil Nadu has the highest share of unallocated power even as I speak here today.

Sir, an issue was raised by Mr. Reddy about PPAs and FSAs. It is the first subject I addressed today. That's the chicken and egg problem I inherited. You were not there in the House, Sir. You are not allowed to sign a PPA if you don't have FSA and they won't give FSA if you don't have PPA.

DR. T. SUBBARAMI REDDY: You solve the problem. You are a dynamic Minister. You must solve the problem.

SHRI PIYUSH GOYAL: Obviously, if I have raised it, I know that I am going to solve it. I am not a person who shies away from problems, Sir. But I have mentioned that this is a legacy that you left for me. But I assure you that I will resolve it.

Sir, hon. Member Shri Athawale spoke about the nuclear projects, particularly Jethapur. While nuclear does not come under my Ministry, I am part of the Government and I must mention that the Government is seized of all the person's concerns about nuclear energy. We are not rushing into any decision for or against. As I mentioned earlier, we have an open mind and with an open mind, considering all the concerns of the people of India, all hon. MPs and the State Governments, final decisions will be taken at the appropriate time.

Budania*ji* raised the issue of solar power. I am extremely happy to report that I have already been in dialogue with their Government, Sir, and I have requested them to identify line so that you could be included, your State could be included in the first lot of solar mega projects and the response has been very positive. I am quite confident. We will resolve that matter.

Sir, you also raised about the Vibrant Gujarat Summits. I am an investment banker

[Shri Piyush Goyal]

before I lost my job and I came over here, Sir. For your kind information, Sir, the period 2000 to 2009 was a period of great enthusiasm. The world was looking to India. But the actions of India in the subsequent years have caused this distress where nobody in the world wanted to come in the last five years and invest in India. So I think it is a matter you will have to reflect on. You will have to find out why people did not come despite such an enabling environment in Gujarat. However, I can assure you that the mood has changed. The world is now looking towards India. Investors are flocking to India and you will see a lot of investments in the months and years to come.

Sir, there was a question by Md. Shafi Sahab about the NHPC projects. सर, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि प्रोजेक्ट में सिर्फ कितने पैसे की बिजली बेची और कितना पैसा लगा - ये दो मापदंड नहीं होते हैं । प्रोजेक्ट चलाने के लिए ब्याज लगता है और प्रोजेक्ट चलाने के लिए Operation maintenance cost लगती है । जब कोई प्रोजेक्ट लगता है, तो उसके सभी खर्चे लेते हुए, जब उसे बेचा जाता है तो उस बिजली के छोटे रिटर्न के साथ रेवेन्यू मिलता है । सर, आपके राज्य में 60 प्रतिशत से अधिक transmission and distribution loss और चोरी है । ये सभी प्लांट्स लॉस में चल रहे हैं क्योंकि ये जिस बिजली का उत्पादन करते हैं, उसका भुगतान, उसका कलैक्शन कम है । मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा कि पहले टी. एंड डी. लॉसेस और चोरी रोकने में मदद करें । उस ओर ध्यान दें। जहां तक प्रोजेक्ट्स ट्रांसफर करने की बात है, ये प्रोजेक्ट्स एक independent autonomous कंपनी के हैं और एनएचपीसी इस प्रकार की सरकारी कंपनी नहीं है कि वह उसे आपको ट्रांसफर कर सके । अगर राज्य सरकार इस कंपनी से खरीदना चाहे तो हमारा open mind है । **...(व्यवधान)...**

MR. DEPUTY CHAIRMAN: It is alright. No clarification on clarification. Sit down.

श्री पीयूष गोयल : अभी तक राज्य सरकार से हमारे पास कोई प्रपोजल नहीं आया है to transfer these projects to the State Government. राज्य सरकार से हमारे पास जब कोई प्रोजेक्ट आएगा, तो उस पर हम गंभीरता से विचार करेंगे। **...(व्यवधान)...** मैं उस पर आ रहा हूं । उसे मैंने लास्ट में इसलिए रखा है कि बाकी सवालों का जवाब देने का मुझे मौका मिलेगा या नहीं, मुझे भरोसा नहीं है ।

सर, स्वामी जी ने कोयले की कमी का विषय उठाया। हमें इस के बारे में पूरी चिंता है । सर, अगर आप नरेंद्र मोदी जी के भाषण सुनें, तो उन्होंने सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, हाइडल, बॉयो-गैस जो भी renewable energy के फॉर्म्स सरकार इस विषय में तेजी से कदम उठा रही है । मैंने जो 2000 मेगावाट्स की चर्चा की, यह तो renewable energy को सपोर्ट देने की बात की है, लेकिन इस देश में सौर ऊर्जा बड़े भारी पैमाने पर लगे, उसके लिए हम बहुत कदम उठा रहे हैं । We are going to offer you a bagful of peanuts, not just one peanut.

Finally, श्री राम नारायण डूडी जी ने भी सौर ऊर्जा की बात की । हम सौर ऊर्जा की बात की । हम सौर और पवन ऊर्जा का राजस्थान में तेजी से उत्पादन करेंगे ।

जहां तक एससी/एसटी और ओबीसी के बैकलॉग का सवाल है, इसकी पूरी जानकारी अभी मेरे पास नहीं है । लेकिन अगर बैकलॉग है, तो मैं उसे गंभीरता से देखूंगा, उसके लिए आवश्यक जरूरी कदम उठाऊंगा और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि हमारी सरकार उनके उत्थान के लिए पूरे तरीके से काम करेगी ।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Hon. Members, the consensus is that the Short Duration Discussion will be taken up later; it is not cancelled. It is only postponed.

Now, Dr. Harsh Vardhan to make a statement on Ebola Virus disease.

STATEMENT BY MINISTER — *Contd.*

Ebola virus disease outbreak in West Africa and steps taken by Government to protect Indian citizens

THE MINISTER OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (DR. HARSH VARDHAN): Sir, I would like to brief the hon. members on the reports of Ebola virus disease outbreak in West Africa and the action taken by the Government of India in this regard.

The World Health Organization has reported 1603 cases, including 887 deaths (as on 4t August, 2014), in West Africa from 4 countries namely Guinea, Liberia, Sierra Leone and Nigeria. While the number of cases is 485, 468, 646 and 4 from the said countries, the number of deaths is 358,255,273 and 1 respectively.

Ebola virus is a Filovirus with 5 distinct species. The specific virus isolated in the current outbreak is Zaire Ebola Virus. Ebola Virus Disease is a severe, often fatal illness with Case Fatality Rate of up to 90 per cent. In Africa, fruit bats are known to carry Ebola virus from whom the animals (chimpanzees, gorillas, monkeys, forest antelopes) get infected. Humans get the infection either from the infected animals or from infected humans when they come in close contact with infected body fluids or body secretions. There is no airborne transmission. During the current outbreak, most of the disease has spread through human to human transmission. The incubation period of Ebola virus disease is 2-21 days, during which the affected persons are not infective.

The Director General of Health Services, Government of India, has reviewed the situation on 2nd May, 2014 and on 1st August, 2014. Thereafter, advisories were issued to the State Disease Surveillance Units to be on alert for early detection and management of travel related cases reported from the community. Laboratory capacity was also strengthened at National Institute of Virology, Pune, and National Centre for Disease Control, Delhi, to diagnose this viral disease.

The Ministry of External Affairs has informed that there are about 4700 Indians in Republic of Guinea, Liberia and Sierra Leone from where maximum cases are reported. The number in each of these countries is 500, 3000 and 1200 respectively. The figure for Liberia includes about 300 personnel from the Indian Central Reserve Police Force,